साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू समाचार पत्र | जयपुर से प्रकाशित

उम्मीद की एक नई रोशनी

आवाज़ ए तसनीम

tasneemtv.official@gmail.com | آوازِ تسنیم | PRGI No. RJBIL/25/A1815

www.tasneemtv.com | वर्षः 02 / अंकः 15 | जयपुर, सोमवार, 26 अक्टूबर , 2026 | पृष्ठ : 8 | मूल्यः 2 रूपए | प्रातः कालीन

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खाटूश्याम जी में सुना मन की बात कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद

मुख्यमंत्री ने कहा-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान को 4 महत्वपूर्ण जल समझौतों की मिली सौगात

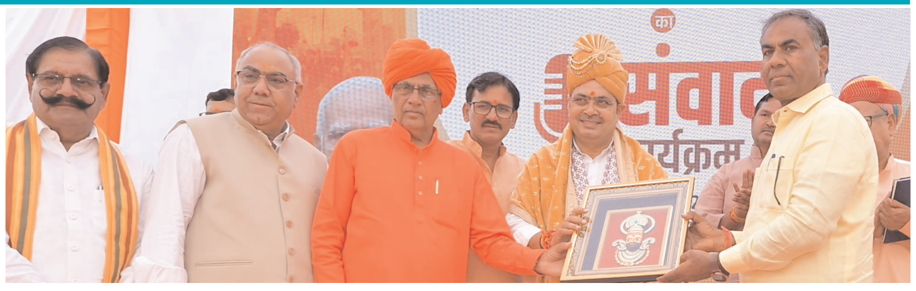

राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन बढ़ाया, युवाओं को दिया रोजगार

सीकर जिले के समग्र विकास के लिए लगभग 7 हजार करोड़ के विकास कार्यों को दी गति

शेखावाटी की 662 ऐतिहासिक हवेलियों को सहेज रही सरकार

हरियाणा चुनावों में कांग्रेस ने कही थी यमुना जल समझौता रद्द करने की बात, प्रदेश के कांग्रेस नेता भी थे इसमें शामिल

बाबा श्याम की कृपा से हंसियावास में बन रहा 800 करोड़ रुपये की लागत का रिजर्वायर

आवाज़ ए तसनीम

सीकर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सीकर के खाटूश्यामजी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 139वां ऐपिसोड सुना। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद में कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार मिलकर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। राजस्थान फसलों, दलहन, तिलहन व फलों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना को बढ़ावा दे रही है। जिससे वोकल फॉर लोकल का संकल्प साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत भी मिलेगी। इसी प्रकार डेयरी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। दूध की प्रसंस्करण यूनिट्स की क्षमता को बढ़ाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में जल की भरपूर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मध्यप्रदेश के साथ ईआरसीपी का समझौता हुआ, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। शेखावाटी क्षेत्र के लिए हरियाणा राज्य के साथ यमुना जल समझौता किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इस समझौते को रद्द करने की बात कही और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शामिल थे। उन्होंने कहा कि खाटूश्याम जी की कृपा से ही यमुना जल समझौते के तहत हंसियावास में 800 करोड़ रुपये की लागत से रिजर्वायर बन रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार राज्यों के बीच में नर्मदा समझौता हुआ और इसी प्रकार शेखावाटी सहित अन्य क्षेत्रों के लिए किसाऊ परियोजना का समझौता भी सम्पन्न हुआ है। इन महत्वपूर्ण समझौतों से शेखावाटी क्षेत्र में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में सोम-कमला-अम्बा, देवास, ब्राह्मणी नदी परियोजना पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने 10 लाख सदस्य जोड़े हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। हमारी सरकार ने ढाई साल में कांग्रेस सरकार के मुकाबले तीन गुना अधिक बिजली उत्पादन किया है, जिससे प्रदेश में पर्याप्त बिजली सप्लाई हो रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार कोटपूतली-किशनगढ़ और बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेस-वे बना रही है। इनसे शेखावाटी सीधे नेशनल हाईवे से जुड जाएगा, जिससे व्यापार बढ़ेगा, किसानों को फायदा होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शेखावाटी की पुरानी और ऐतिहासिक हवेलियां यहां के पर्यटन और विकास की बडी ताकत हैं। हमारी सरकार शेखावाटी की 662 हवेलियों को संभालने और सहेजने का काम कर रही है। इसीलिए हेरिटेज टूरिज्म सर्किट बनाने के लिए 8 दिसम्बर को शेखावाटी में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रवासी राजस्थानी आएंगे। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की मदद से कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में 61 हजार से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि सीकर जिले के समग्र विकास के लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के युवाओं को सरकारी नौकरियों के माध्मय से रोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमारी सरकार ने अब तक 1.93 लाख पदों पर नियुक्तियां दी हैं और 1.18 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इन भर्तियों में शेखावाटी क्षेत्र के युवाओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय पेपरलीक होते थे, जबकि हमारी सरकार में 410 परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता से बिना पेपरलीक के सम्पन्न कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राष्ट्रीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी है। प्रदेश 12 राष्ट्रीय योजनाओं में पहले, 10 योजनाओं में दूसरे तथा 8 योजनाओं में तीसरे स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आमजन ने समर्थन देकर डबल इंजन सरकार के साथ तीसरा इंजन जोड़ा है। इसी प्रकार पंचायत चुनावों में भी जनता विकास कार्यों को गति देने के लिए तीसरा इंजन जोड़ेगी। उन्होंने हमारी सरकार ने वन स्टेट-वन इलेक्शन कराने का जो वादा किया था, वह आज पूरा हो रहा है।

वाराणसी एयरशोः विमानों की गर्जना से गूंजा आकाश, प्रधानमंत्री मोदी का लोगों ने जताया आभार, बोले-अद्भुत-अकल्पनीय

आवाज़ ए तसनीम

वाराणसी। काशी के नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के एयरशो का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान फाइटर जेट्स की गर्जना से आसमान गुंजायमान हो उठा।

विमानों के करतब ने सबको हैरान कर दिया। पीएम मोदी भी इसके साक्षी बने।

वाराणसी के लोगों ने इस आयोजन को अद्भुत बताया। साथ ही पीएम मोदी का आभार जताया।

पीएम मोदी के साथ ही रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी भी मौजूद रहे। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी को स्मृति चिन्ह दिया। इसके बाद पीएम मोदी ने भी एयर शो का लुत्फ़ उठाया। रविवार का अंतिम शो बेहद अदभुत रहा। रविवार के शो की बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान और लड़ाकू विमानों ने भाग लिया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भुवनेश्वर में आरबीआई के नवनिर्मित डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया

जैसे-जैसे भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, हमें अपने बैंकिंग तंत्र को साइबर लुटेरों और साइबर आतंकियों से बचाना होगाः प्रधानमंत्री मोदी

आवाज़ ए तसनीम

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रविवार को भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया।

उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर आज नए भारत को एक नया संस्थान दे रहा है। उन्होंने आरबीआई के डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान को महत्वपूर्ण बताते हुए इससे जुड़े सभी लोगों को बधाई दी।

गांवों और छोटे शहरों के विकास पर जोर

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने लोगों को केंद्र में रखकर और तेजी से काम करने वाली बेहतर शासन व्यवस्था का मॉडल अपनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए विकास का मतलब पूरे भारत का संतुलित विकास है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि गांवों और छोटे शहरों में भी नए अवसर पैदा करना, दूर-दराज के इलाकों तक बेहतर संपर्क पहुंचाना और गरीब परिवारों को सम्मान के साथ जीवन जीने का मौका देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज देश के एक्सप्रेसवे छोटे शहरों को भी जोड़ रहे हैं। एम्स जैसी स्वास्थ्य संस्थाओं का कई राज्यों में विस्तार किया गया है और छोटे शहरों में मेडिकल कॉलेज भी बनाए जा रहे हैं।

पहले फोन बैंकिंग से कुछ खास लोगों को मिलता था फायदा

प्रधानमंत्री ने 2014 से पहले की बैंकिंग व्यवस्था पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उस समय फोन बैंकिंग का एक अलग दौर था। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में कांग्रेस के करीबी कुछ लोग हजारों करोड़ रुपये का बैंक कर्ज आसानी से हासिल कर लेते थे, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बैंक खाता खोलने के लिए भी गारंटी की जरूरत पड़ती थी।

उन्होंने कहा कि उस समय प्रभावशाली लोगों को हजारों करोड़ रुपये का कर्ज दिया गया। इसका असर देश के बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ा और बैंकों पर फंसे हुए कर्ज यानी एनपीए का बोझ बढ़ गया।

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का बैंकिंग क्षेत्र दुनिया के मजबूत बैंकिंग क्षेत्रों में शामिल है। उन्होंने कहा कि पहले बैंकिंग सेवाओं का फायदा प्रभावशाली लोगों तक सीमित था, लेकिन आज डिजिटल बैंकिंग के जरिए देशभर के परिवार बैंकिंग सेवाओं का फायदा उठा रहे हैं।

अब दिल्ली से भेजा एक रुपया पूरा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है

पीएम मोदी ने ओडिशा का जिक्र करते हुए कहा कि यहीं की धरती से देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से भेजे गए एक रुपये में से सिर्फ 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, अब जब दिल्ली से एक रुपया भेजा जाता है, तो पूरी राशि उस लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय डेबिट और क्रेडिट कार्ड को अमीर लोगों की चीज माना जाता था, लेकिन आज देश के हर नागरिक के लिए इनकी पहुंच आसान हुई है।

देशभर में करोड़ों डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं।

25 हजार करोड़ रुपये बिना किसी शोर के लोगों तक पहुंचे

पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरी सरकार इतनी बड़ी रकम बांटने का ऐलान करती, तो कई महीनों तक इसका प्रचार होता।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान यह पैसा मुश्किल समय में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों तक बिना किसी शोर-शराबे के पहुंच रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यही सुशासन का मतलब है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने पर ध्यान दिया गया, जो पहले इनसे दूर थे।

अब आने वाले 10 साल में बैंकिंग व्यवस्था को और बेहतर और भरोसेमंद बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओडिशा में बनाया गया नया डेटा सेंटर इस काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बैंकिंग व्यवस्था को साइबर हमलों से बचाना जरूरी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षित रखना है तो उसकी डिजिटल व्यवस्था की सुरक्षा भी जरूरी है। इसके लिए मजबूत डेटा सेंटर और बेहतर कंप्यूटर व्यवस्था की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं लड़े जाते। किसी देश की अर्थव्यवस्था पर हमला करके भी उसे कमजोर किया जा सकता है।

पीएम मोदी ने कहा कि जैसे-जैसे भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, वैसे-वैसे देश की बैंकिंग व्यवस्था को साइबर अपराधियों और साइबर आतंकवादियों से बचाना भी जरूरी हो गया है।

पुरानी व्यवस्था से नई साइबर चुनौतियों का मुकाबला नहीं होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर खतरे लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में पुरानी व्यवस्था, पुराने प्रशिक्षण के तरीके और पुराने उपकरणों से इन नई चुनौतियों का सामना नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि देश को आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ ऐसे लोगों की भी जरूरत है, जिनके पास साइबर सुरक्षा से जुड़ी जरूरी जानकारी और कौशल हो।

पीएम मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में शुरू किया गया नया साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के निर्माण में पूर्वी भारत को विकास का एक सशक्त इंजन बताते हुए कहा कि ओडिशा में वर्तमान सरकार के नेतृत्व में विकास कार्यों को नई गति मिली है।

उन्होंने कहा कि राज्य अपने पारंपरिक खनिज-आधारित उद्योगों के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और उन्नत कंप्यूटिंग के नए इकोसिस्टम को विकसित कर रहा है।

इस तरह ओडिशा खदानों से लेकर माइक्रोचिप तक की विकास यात्रा के माध्यम से अपने भविष्य के बड़े अवसर बना रहा है।

कांग्रेस को चुनाव में जीत मिलती है, तो उसे वोट चोरी याद नहीं आती, लेकिन हारने पर वो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती हैं : संजय भाटिया

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। भाजपा के प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से 1 नवंबर को प्रस्तावित महारैली को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने झूठ को बचाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को चुनाव में जीत मिलती है, तो उसे वोट चोरी याद नहीं आती, लेकिन हारने पर वो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगती है। भाटिया ने रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही।

इस दौरान सांसद मंजू शर्मा सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कांग्रेस को जीतने पर वोट चोरी याद नहीं आती :

कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए संजय भाटिया ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में चुनाव जीतती है, तब उसे वोट चोरी की बात याद नहीं आती। नगरीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ज्यादा वोट मिलने का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस तरह के आरोप लगाने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए।

उसे अपनी गलतियों और सरकार के कार्यकाल की समीक्षा करनी चाहिए। भाटिया ने कहा कि झूठे आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा।

चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं तो पंचायत चुनाव क्यों?

चुनाव आयोग पर विपक्ष के आरोपों को लेकर भाटिया ने सवाल किया कि यदि कांग्रेस को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो वो पंचायत चुनाव क्यों लड़ रही है?

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को अपने रुख पर विचार करना चाहिए। भाटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी देश में कोई रिफॉर्म होता है, कांग्रेस उसका विरोध करती है।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में आया बदलावः नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटिया ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय अनुच्छेद 370 लागू किए जाने से कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। अब अनुच्छेद 370 हटने के बाद वहां परिस्थितियों में बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि पहले श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना मुश्किल था, जबकि अब वहां बदलाव दिखाई देता है। नवरात्रि जैसे पर्वों पर भी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। भाटिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में होने वाले बदलावों और विकास कार्यों का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को देश की तरक्की में सहयोग करना चाहिए, न कि हर सुधार पर सवाल उठाना चाहिए।

ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को घेराः भाटिया ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के सवालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सेना की कार्रवाई के सबूत मांगने से जवानों का मनोबल प्रभावित होता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को स्वीकार करता है और क्या वो भारत की सफलता को मानता है? भाटिया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा का विरोध करते-करते विपक्ष देश का विरोध करने लगता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी चाहिए।

मन की बात में मेक इन इंडिया की सराहनाः इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल पर जोर देते रहे हैं। उनके अनुसार, भारत की उत्पादन क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि हुई है। पहले देश को रक्षा उपकरणों और हथियारों की आपूर्ति के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जबकि अब भारत कई देशों को अपने उत्पादों और रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने इसे देश की बढ़ती आर्थिक ताकत और आत्मनिर्भरता का संकेत बताया।

केरल का यह मदरसा बना हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल

ओनिका माहेश्वरी/ नई दिल्ली । आधुनिकता की दौड़ और कई बार समाज में बनाई जाने वाली दूरियों के बीच, दक्षिण भारत के केरल राज्य से एक ऐसी तस्वीर उभरकर सामने आई है, जो दिल को गहराई से झकझोर देती है और चेहरे पर एक सुकूनभरी मुस्कान ले आती है। केरल के पलक्कड़ जिले के शांत और हरियाली से घिरे वाणियमकुलम) क्षेत्र में स्थित 'मानु मुसलीयार इस्लामिक कॉम्प्लेक्स' (स्र्ख्र्ह्रष्ट - जामिया रहीमिया) आज केवल एक शैक्षणिक या धार्मिक संस्थान भर नहीं रह गया है, बल्कि यह देश भर के लिए सांप्रदायिक सौहार्द, अटूट विश्वास और इंसानी भाईचारे का एक ऐसा जीवंत प्रकाशपुंज बन चुका है, जहाँ सरहदें और मजहबी दीवारें इंसानियत के सामने स्वतः ढह जाती हैं।

एक युवती की आँखों में तैरते अवाक कर देने वाले भाव और आत्मीयता का अहसासइस खूबसूरत बदलाव और गंगा-जमुनी तहजीब की असली रूह को बयां करती एक घटना ने इन दिनों हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जब केरल की एक युवा युवती ने इस मदरसे के प्रांगण में कदम रखा, तो वहाँ के दृश्यों ने उनकी सोच को एक नया आयाम दे दिया। उनके भीतर आश्चर्य, अविश्वास और अगाध भावुकता का एक ऐसा ज्वार उमड़ पड़ा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी आँखों से देखा कि कैसे एक धार्मिक ।

वर्ष 1989 में की गई थी। इसकी परिकल्पना और आधारशिला केरल के विख्यात इस्लामिक विद्वान, महान समाज सुधारक और शिक्षाविद् के.टी. मानु मुसलीयार के पवित्र विचारों और उनकी स्मृति में रखी गई थी। के.टी. मानु मुसलीयार ने अपने जीवनकाल में केरल के प्रतिष्ठित संगठन 'समस्ता केरल इस्लाम मता विद्याभ्यास बोर्ड' के जनरल सेक्रेटरी के रूप में ऐतिहासिक सेवाएं दी थीं। उनका स्पष्ट मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्रियां बांटना नहीं है, बल्कि इंसानों के दिलों में नैतिक मूल्यों और आपसी भाईचारे का बीज बोना है।

आज उनकी यही दूरदर्शी सोच इस परिसर के चप्पे-चप्पे पर जीवंत नजर आती है।सांस्कृतिक समन्वय का उत्सवः जहाँ मिलकर पकता है और बँटता है लंगरकेरल की पारंपरिक 'गंगा-जमुनी तहजीब'—यानी विभिन्न धर्मों के त्योहारों, सुख-दुख और उत्सवों में एक-दूसरे के गले मिलने की परंपरा—का यह संस्थान सबसे बेहतरीन मॉडल पेश करता है। यहाँ चलने वाले विशाल सामुदायिक लंगर और भोजनशाला की संस्कृति ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। इस रसोई में न तो कोई धर्म पूछा जाता है और न ही कोई जात। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और ईसाई—तीनों प्रमुख समुदायों के लोग कंधे से कंध? मिलाकर, पूरे प्रेम और उत्साह के साथ एक ही चूल्हे पर खाना पकाते हैं।

भोजन तैयार होने के बाद विभिन्न पृष्ठभूमियों के स्वयंसेवक मुस्कुराते हुए लोगों को लंगर परोसते हैं। सबसे जादुई और भावुक कर देने वाला पल तब आता है जब समाज के हर वर्ग के लोग, बच्चे, बुजुर्ग और युवा एक लंबी कतार में और एक ही मेज पर बैठकर एक ही थाली में भोजन साझा करते हैं। उस युवती ने जब इस पवित्र नजारे को अपनी आँखों से निहारा, तो वह समझ गई कि यह केवल पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि इंसानी दिलों को जोड़ने का एक ऐसा पावन उत्सव है जो शब्दों से परे है।

अक्टूबर 2026 का ऐतिहासिक सम्मेलन

जब गूंजा एकता और शांति का संदेशसंस्थान की परंपराओं में इसके वार्षिक आयोजन मील का पत्थर साबित होते हैं। हाल ही में अक्टूबर 2026 में इस परिसर में 37वां वार्षिकोत्सव और 13वां सनद दान (दीक्षांत) सम्मेलन अत्यंत भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक आयोजन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह थी कि इसमें केवल एक मजहब या वर्ग के लोग शामिल नहीं हुए, बल्कि विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों के दिग्गज बुद्धिजीवियों और नेताओं ने शिरकत की।मंच से उठी हर एक आवाज ने देश में शांति, आपसी विश्वास और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने का संकल्प लिया, जिसने पूरे क्षेत्र में प्रेम की एक नई बयार बहा दी।संस्थान की मजबूत शैक्षणिक नींव और बहुमुखी ताकत'मानु मुसलीयार इस्लामिक कॉम्प्लेक्स' केवल लंगर और मेल-मिलाप तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मजबूत और समावेशी शिक्षा प्रणाली है।

यह संस्थान अनाथ, बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है:समावेशी और नैतिक शिक्षाः यहाँ बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च नैतिक मूल्य सिखाए जाते हैं, ताकि वे भविष्य में समाज के एक जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक बन सकें।विविध और उन्नत पाठ्यक्रमः परिसर के भीतर प्राथमिक मदरसे से लेकर पवित्र कुरआन को कंठस्थ कराने वाला 'हिफ्जुल कुरआन कॉलेज' और उच्च इस्लामी अध्ययन के लिए 'जामिया रहीमिया अरबी कॉलेज' सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं।बहुभाषी ज्ञान और आधुनिक संसाधनः छात्रों को अरबी, अंग्रेजी, उर्दू और मलयालम जैसी भाषाओं में पारंगत किया जाता है।

तीन बच्चों की मां रुख्सार खान ने योग से बनाई अलग पहचान

आवाज ए तसनीम

भक्ति चालक। उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर हुसैनाबाद से आई एक मुस्लिम लड़की। उसने सिर्फ बारहवीं तक तालीम हासिल की और कम उम्र में ही उसकी शादी भी हो गई। आज वह मुंबई में महिलाओं को सेहत और फिटनेस की तालीम दे रही है। ज़िंदगी में ज़िम्मेदारियों का पहाड़, तीन बच्चों की परवरिश और बीमारियों की चुनौतियों का सामना करते हुए उसने खुद को साबित किया है। यह कहानी है मुंब्रा की योग ट्रेनर और हेल्थ कोच रुख्सार खान की।

रुख्सार का बचपन उत्तर प्रदेश में गुज़रा। उनके वालिद जूते-चप्पल की दुकान में सेल्समैन की नौकरी करते थे। एक भाई और चार बहनों में वह सबसे बड़ी हैं। उनकी वालिदा एक हाउसवाइफ हैं, लेकिन उन्होंने खुद के ख्वाबों को किनारे रखकर बच्चों की तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश की। रुख्सार भाई-बहनों में सबसे बड़ी थीं, इसलिए अठारह साल की उम्र पूरी होते ही उनकी शादी हो गई और वह महाराष्ट्र आ गईं।

जहां चाह, वहां राह

अक्सर महिलाएं शादी या बच्चे होने के बाद अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ देती हैं। उम्र बढ़ने पर सोचती हैं कि 'अब हमारी ज़िंदगी में क्या बचा है।' लेकिन रुख्सार खान ने इस सोच को गलत साबित कर दिया। मुश्किल हालात को मात देते हुए उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 'आवाज़-द वॉयस' से बात करते हुए उन्होंने अपने इस संघर्ष से भरे और बेहद प्रेरणादायक सफर के बारे में बताया।

घर की इकलौती बहू होने की वजह से परिवार की सारी ज़िम्मेदारियां उन पर आ गईं। इस भागदौड़ में तालीम का सिलसिला टूट गया और बारहवीं के बाद की पढ़ाई अधूरी रह गई। दोनों चीज़ों के बीच तालमेल न बिठा पाने की वजह से उन्होंने पढ़ाई पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी। लेकिन दिल में कुछ सीखने और कुछ करने की ज़िद हमेशा कायम रही।

रुख्सार कहती हैं, 'मुझे ज़िंदगी में एक बात बिल्कुल साफ पता थी; जो भी करना है वह पूरी ताक़त और 100 फीसद देकर करना है, वरना करना ही नहीं है। वक्त बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है। '

बेटे की पढ़ाई से हुई ट्यूशन की शुरुआत

घर के कामों में उलझी रुख्सार की ज़िंदगी में पहला मोड़ तब आया जब उनका बड़ा बेटा स्कूल जाने लगा। रुख्सार उसे खुद घर पर पढ़ाती थीं। मां से पढ़ते-पढ़ते बच्चे की पढ़ाई में काफी सुधार दिखने लगा। बेटे का अच्छा रिज़ल्ट देखकर पड़ोसियों ने रुख्सार से ट्यूशन के बारे में पूछा।

इस तरह पड़ोसियों ने अपने बच्चों को रुख्सार के पास पढ़ने के लिए भेजना शुरू कर दिया। यहीं से उनके होम ट्यूशन का सफर शुरू हुआ। कुर्ला में रहते हुए उन्होंने लगातार 9 साल तक छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया।

योगा के मैदान में पहला कदम

कुछ सालों बाद रुख्सार का परिवार कुर्ला से मुंब्रा शिफ्ट हो गया। वहां आने पर पानी और मौसम के बदलाव की वजह से उन्हें सेहत से जुड़ी परेशानियां होने लगीं। बार-बार बीमार पड़ने से वह काफी तंग आ चुकी थीं। फिटनेस का शौक पहले से ही था, इसलिए अपनी सेहत सुधारने के लिए उन्होंने एक मुकामी योगा स्टूडियो जाने का फैसला किया।

लेकिन वहां जाने पर उन्हें नज़ारा बिल्कुल अलग दिखा। लोग सिर्फ आ-जा रहे थे, योगासन गलत तरीके से किए जा रहे थे और किसी को भी इसके बारे में सही जानकारी नहीं थी। यह देखकर रुख्सार के अंदर का सीखने वाला जज़्बा फिर से जाग उठा।

इस बारे में रुख्सार बताती हैं, 'हम अपना एक घंटा दे रहे हैं, लेकिन सेहत को कोई फायदा नहीं हो रहा है, यह देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। वहीं मैंने तय किया कि मुझे इसकी सही तालीम हासिल करनी है और एक परफेक्ट हेल्थ कोच बनना है। '

डोंबिवली में ली योगा की तालीम

खुद को साबित करने के मक़सद से रुख्सार सीधे मुंब्रा से डोंबिवली गई और वहां योगा की शास्त्रीय तालीम लेनी शुरू की। उन्होंने शरीर की बनावट (ठ्ठड्डह्लशद्व4), अलग-अलग बीमारियों और योगा के सही फॉर्म्स का गहराई से मुताला किया।

रुख्सार ने योगा में ट्रेनिंग पूरी करके ऑफिशियल सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया। प्रैक्टिकल और डेमो क्लासेज़ में उनका परफॉरमेंस इतना शानदार रहा कि जिस स्टूडियो में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, उसी संस्था ने उन्हें वहीं ट्रेनर के तौर पर नौकरी दे दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने 'फिटनेस योगशाला' के नाम से अपना खुद का योगा स्टूडियो शुरू कर दिया और महिलाओं को ट्रेनिंग देना शुरू किया।

इस पूरे सफर में रुख्सार के शौहर इमरान खान उनकी ढाल बनकर खड़े रहे। इमरान पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और अपना खुद का बिज़नेस चलाते हैं। इसलिए वह भी चाहते थे कि रुख्सार अपने पैरों पर खड़ी हों। चाहे रात में पढ़ाई करनी हो या क्लास आने-जाने की सहूलियत हो, उनके शौहर ने हर कदम पर उनका पूरा साथ दिया।

समाज की गलतफहमियों को किया दूर

योगा के मैदान में काम करते वक्त रुख्सार के सामने एक बड़ी समाजी रुकावट थी। मुस्लिम समाज में योगा को लेकर कई गलतफहमियां थीं। बहुत से लोगों को लगता था कि योगा एक खास मज़हब से जुड़ा हुआ व्यायाम है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए रुख्सार ने पहल की।

उन्होंने अपने काम से साबित कर दिया कि व्यायाम या सेहत का किसी भी मज़हब से सीधा कोई ताल्लुक नहीं होता। गैर-मुस्लिम महिलाओं के लिए क्लास लेते वक्त वह रिवायती तरीके से श्लोक और ?कार का जाप करवाती थीं। वहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने उनके आस्था से जोड़कर मेडिटेशन का एक नया और असरदार तरीका शुरू किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए आयतें पढ़नी शुरू कीं। इससे महिलाओं का योगा को देखने का नज़रिया पूरी तरह बदल गया।

योगा किसी मज़हब का नहीं होता, यह समझाते हुए रुख्सार कहती हैं, 'मैंने महिलाओं को सिर्फ एक ही बात समझाई कि जब तक हम दिल में ऐसा खयाल नहीं लाते, तब तक व्यायाम का कोई मज़हब नहीं होता। योगा से हमारी रूहानी ताक़त बढ़ती है। योगा जिस्म को तरोताज़ा रखता है और हम फिट रहते हैं। '

फारूक अब्दुल्ला के बयान का नसीरुद्दीन चिश्ती और गुलाम नबी आजाद ने किया विरोध

आवाज ए तसनीम

किशोर सिंह सोलंकी/ अजमेर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पाकिस्तान संबंधी बयान पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अजमेर दरगाह से जुड़े नसीरुद्दीन चिश्ती ने अब्दुल्ला की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी पाकिस्तान को कश्मीर का रक्षक बताए जाने के विचार से असहमति जताई है।

दोनों की प्रतिक्रिया का मुख्य आधार पाकिस्तान की भूमिका को लेकर असहमति है। चिश्ती ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, हिंसा और भारतीय जवानों की शहादत का उल्लेख करते हुए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर, गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर का मददगार बताना सही नहीं है। उनके मुताबिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों की स्थिति को भी इस बहस में ध्यान में रखना चाहिए।

फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है कि कश्मीर के राजनीतिक भविष्य, आतंकवाद और भारत पाकिस्तान संबंधों को किस नजरिये से देखा जाना चाहिए।

नसीरुद्दीन चिश्ती ने पाकिस्तान की भूमिका पर उठाए सवाल

अजमेर दरगाह से जुड़े नसीरुद्दीन चिश्ती ने फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी पर असहमति जताते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और हिंसा के कारण बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान गई है। उन्होंने भारतीय जवानों की शहादत का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर के लोगों का मददगार बताना उचित नहीं है।

चिश्ती के मुताबिक, जम्मू कश्मीर के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से प्रभावित परिवारों के दुख और बलिदान को ध्यान में रखना जरूरी है।

उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की भूमिका को लेकर किसी भी चर्चा में कश्मीर में हुई हिंसा और उसके सामाजिक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

गुलाम नबी आजाद बोले, पाकिस्तान रक्षक नहीं

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी फारूक अब्दुल्ला के बयान पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला लंबे समय तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं और कई बार मुख्यमंत्री के साथ केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें इस तरह की टिप्पणी की उम्मीद नहीं थी।

आजाद ने कहा, 'मैं इस दावे से पूरी तरह असहमत हूं कि पाकिस्तान हमारा रक्षक है। पाकिस्तान हमारा विनाश करने वाला है, रक्षक नहीं। '

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाना और वहां के लोगों के लिए रोजगार तथा कारोबार के अवसर पैदा करना दो अलग बातें हैं। उनके मुताबिक, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

आजाद ने दावा किया कि वहां के लोग पाकिस्तान से मुक्ति चाहते हैं और भारत के साथ जुड़ने की इच्छा रखते हैं। यह उनका राजनीतिक आकलन है। इस दावे को सभी स्थानीय लोगों की राय नहीं माना जा सकता।

विकास और आतंकवाद पर भी छिड़ी बहस

गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में हुए विकास का श्रेय केंद्र की विभिन्न सरकारों को दिया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि अलग अलग सरकारों ने क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।

उन्होंने सड़कों, सुरंगों, राजमार्गों और रेल संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाओं का जिक्र किया। साथ ही, उन्होंने जम्मू कश्मीर में दशकों से चली आ रही हिंसा और आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया।

इस तरह फारूक अब्दुल्ला के बयान पर उठे सवाल अब केवल पाकिस्तान की भूमिका तक सीमित नहीं हैं। इनके केंद्र में जम्मू कश्मीर का विकास, आतंकवाद से प्रभावित परिवारों का दर्द और क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण भी हैं।

कश्मीर की राजनीति में बयान का क्या महत्व है?

फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी पर आई प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की भूमिका एक संवेदनशील राजनीतिक विषय बनी हुई है। एक तरफ राज्य का दर्जा, निर्वाचित सरकार के अधिकार और केंद्र के साथ संबंधों को लेकर बहस जारी है। दूसरी तरफ आतंकवाद और हिंसा का इतिहास राजनीतिक बयानों को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है।

नसीरुद्दीन चिश्ती और गुलाम नबी आजाद ने अपने अपने नजरिये से फारूक अब्दुल्ला के बयान का विरोध किया है। हालांकि, दोनों की राजनीतिक और सामाजिक भूमिकाएं अलग हैं। उनकी टिप्पणियों को उसी संदर्भ में समझना चाहिए। फिलहाल इस विवाद पर फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी और उस पर उठे सवाल चर्चा में हैं। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस आलोचना पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या अब्दुल्ला अपने बयान के संदर्भ में कोई और स्पष्टीकरण देते हैं।

बिहार में अनोखी शादी : 'बापू' संग 'कस्तूरबा' का निकाह, बैलगाड़ी से ससुराल आई दुल्हन

आवाज ए तसनीम

ओनिका माहेश्वरी/ नई दिल्ली। आज के दौर में जहां शादियों में महंगी गाड़ियों, भव्य सजावट और दिखावे पर खूब खर्च किया जाता है, वहीं बिहार के नवादा जिले में एक शिक्षक ने अपने निकाह को सादगी और पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति से जोड़कर खास बना दिया। यहां दूल्हा अपनी दुल्हन को किसी लग्जरी कार या आधुनिक वाहन से नहीं, बल्कि फूलों से सजी बैलगाड़ी में बैठाकर गांव लेकर आया। इतना ही नहीं, शादी के निमंत्रण कार्ड पर दूल्हा-दुल्हन के नाम की जगह 'बापू संग कस्तूरबा' लिखवाया गया। बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई और शादी के कार्ड पर लिखे इस अनोखे संदेश ने लोगों का ध्यान खींच लिया है।

यह अनोखा निकाह नवादा जिले के रोह प्रखंड स्थित मरुई गांव के रहने वाले शिक्षक एहतेशाम रजा का है। 16 अक्टूबर को निकाह के बाद जब वह अपनी पत्नी जाकरा अकील को फूलों से सजी बैलगाड़ी में लेकर गांव पहुंचे, तो उन्हें देखने के लिए ग्रामीणों, परिजनों और विद्यार्थियों समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। दूल्हा-दुल्हन के इस देसी अंदाज को देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए।

निकाह के बाद बैलगाड़ी से गांव पहुंची दुल्हन

आमतौर पर शादी के बाद दूल्हा-दुल्हन महंगी कारों या सजी-धजी गाड़ियों में घर पहुंचते हैं। कई जगह दूल्हे के लिए खास रथ या अन्य भव्य सवारी का इंतजाम भी किया जाता है। लेकिन नवादा के शिक्षक एहतेशाम रजा ने इस परंपरा से हटकर अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में घर लाने का फैसला किया। 16 अक्टूबर को निकाह के बाद एहतेशाम अपनी पत्नी जाकरा अकील के साथ फूलों से सजी बैलगाड़ी पर सवार होकर मरुई गांव पहुंचे। एहतेशाम ने सफेद शेरवानी और पारंपरिक पगड़ी पहन रखी थी, जबकि उनकी पत्नी जाकरा लाल जोड़े में सजी हुई थीं। बैलगाड़ी को भी फूलों से सजाया गया था, जिससे यह पूरे गांव में आकर्षण का केंद्र बन गई। जब यह अनोखी बारात गांव पहुंची, तो ग्रामीणों के साथ-साथ परिजन और उनके विद्यार्थी भी स्वागत के लिए मौजूद थे। आधुनिक दौर में बैलगाड़ी से दुल्हन को घर लाने का यह नजारा लोगों के लिए अलग अनुभव था। गांव में इस अनोखी सवारी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि, एहतेशाम का यह फैसला केवल लोगों को चौंकाने के लिए नहीं था। इसके पीछे उनकी इच्छा पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति को फिर से जीवंत करने और अपनी जड़ों से जुड़ाव बनाए रखने की थी।

शादी के कार्ड पर लिखा 'बापू संग कस्तूरबा'

एहतेशाम रजा और जाकरा अकील के निकाह में बैलगाड़ी जितनी चर्चा में रही, उतना ही ध्यान उनके शादी के कार्ड ने भी खींचा। आमतौर पर शादी के निमंत्रण पत्र पर दूल्हा-दुल्हन के नाम लिखे जाते हैं, लेकिन इस जोड़े ने अपने कार्ड पर एक अलग ही संदेश छपवाया। कार्ड पर लिखा था 'बापू संग कस्तूरबा'। इस लाइन को पढ़कर कई लोग हैरान रह गए और इसके पीछे की वजह जानना चाहने लगे। दरअसल, 'बापू' महात्मा गांधी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लोकप्रिय संबोधन है, जबकि कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थीं। एहतेशाम ने अपने निकाह के कार्ड पर इन नामों को जगह देकर महात्मा गांधी के प्रति अपनी प्रेरणा और अपनी पत्नी के साथ अपने आत्मीय रिश्ते को व्यक्त किया।

एहतेशाम बताते हैं कि वह महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। वह अपनी पत्नी जाकरा को प्यार से 'कस्तूरबा' कहकर बुलाते हैं, जबकि जाकरा उन्हें 'बापू' कहती हैं। दोनों के बीच इस्तेमाल होने वाले इन प्यार भरे संबोधनों को ही उन्होंने शादी के कार्ड पर लिखवाने का फैसला किया। इस तरह शादी का निमंत्रण पत्र केवल एक औपचारिक कार्ड नहीं रहा, बल्कि उनके रिश्ते और विचारों को दर्शाने वाला खास संदेश बन गया। जहां एक ओर बैलगाड़ी ने ग्रामीण परंपरा की याद दिलाई, वहीं 'बापू संग कस्तूरबा' ने इस निकाह को एक अलग पहचान दी।

जायरीनों का मुस्लिम मुसाफिरखाना में अभिनंदन समारोह, गुलपोशी भी की

आवाज ए तसनीम

बाड़मेर। जायरीनों का मुस्लिम मुसाफिरखाना में अभिनंदन समारोह, गुलपोशी भी की बाड़मेरबाड़मेर 7 मक्का-मदीना की मुकद्दस उमराह यात्रा पूरी कर बाड़मेर लौटे जायरीनों का मुस्लिम समाज ने जोरदार इस्तकबाल किया। शहर के साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग माल गोदाम रोड स्थित मुस्लिम मुसाफिरखाना पहुंचे। जायरीनों को मुबारकबाद दी। यात्रा की खुशी साझा की। मुस्लिम मुसाफिरखाना में हुए कार्यक्रम में जुड़िया खान, मोहम्मद सलीम, हाजी खान, गफार खान, मिसरी खान, मोहम्मद इकबाल, युवा नेत्री शहनाज समा, उम्मत बानो, उमानी बानो, सखीना बानो, इमणा बानो, सलमा बानो, सहेजा बानो, शरीफ खान, नसीबा बानो, रसीदा बानो का स्वागत किया गया। मुस्लिम इंतजामिया कमेटी, थार मुस्लिम एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी, जिला हज कमेटी, समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। जायरीनों की गुलपोशी की गई। गले मिलकर मुसाफा किया गया। मुबारकबाद पेश की गई। हज ट्रेनर बच्चू खान कुम्हार ने बताया कि जिले के सम्मों की ढाणी सोखरू से उमराह पर गए 21 जायरीन वतन लौटे। उनकी वापसी पर बाड़मेर में खुशी का माहौल रहा। लोगों में स्वागत को लेकर खासा उत्साह दिखा।

जम्मू-कश्मीर में अगले सप्ताह मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, मंत्री पद के लिए संपर्क न करें विधायक : उमर

आवाज ए तसनीम

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को कहा कि अगले सप्ताह के शुरुआती दो-तीन दिन में उनके मंत्रिमंडल का विस्तार और उसमें फेरबदल किया जाएगा। अब्दुल्ला ने पार्टी के अपने सहयोगियों और विधायकों से मंत्री पद के लिए संपर्क न करने की अपील करते हुए कहा कि मंत्रियों की सूची पहले ही तय की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने शनिवार सुबह यहां लोक भवन में सिन्हा से मुलाकात की।

अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हां, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा हुई। मैंने उनसे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय मांगा और कहा कि अगले सप्ताह के शुरुआती दो-तीन दिन में मैं मंत्रिमंडल का विस्तार करूंगा और उसमें कुछ बदलाव भी करूंगा।''

उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल इसके लिए समय तय करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा।

مشرقِ وسطیٰ کا محاذ اور یورپ کا بدلتا مزاج

آوازِ تسنیم

اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ''مکّہ دفاعی معاہدے'' کے حوالے سے ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں سعودی عرب، پاکستان اور تُرکیہ نے شرکت کی۔ مذکورہ اجلاس میں یہ اہم ترین فیصلہ کیا گیا کہ سعودی عرب میں پاکستانی اور تُرک افواج تعینات کی جائیں گی۔ اس موقع پر تینوں ممالک کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیے کے مطابق، پاکستان اور تُرکیہ کی دفاعی صلاحیتیں فوری طور پر سعودی عرب منتقل ہوں گی جبکہ حوثی باغیوں کی مکّہ، مدینہ کو نشانہ بنانے کی کوششوں اور دیگر تنصیبات پر حملوں کی بھی شدید مذمّت کی گئی اور اس عمل کو ناقابلِ قبول قرار دیا گیا۔ یاد رہے، ستمبر میں یمنی حوثیوں نے تیز رفتار پیش قدمی کرکے ایسے جزائر اور شہروں پر قبضہ کرلیا تھا کہ جس کی وجہ سے بحرِ احمر کی اہم ترین آبی گزرگاہ، باب المندب میں بحری تجارت کو خطرات لاحق ہوگئے اور بالخصوص سعودی تیل کی ترسیل میں، جو آبنائے ہُرمز کی بندش کے سبب بحرِ احمر سے گزرتا ہے، تعطّل پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہوگیا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یمنی فوج نے مقبوضہ علاقوں کو حوثی باغیوں سے بازیاب کروالیا ہے۔ تاہم، اس دوران حوثیوں نے سعودی تیل کی تنصیبات کو مسلسل نشانہ بنایا، جس سے سعودی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن، جو باب المندب کے ذریعے ٹینکرز تک تیل پہنچاتی ہے، متاثر ہوئی اور اس سے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوگیا۔ یمن میں حوثیوں کی بغاوت 2006 سے جاری ہے۔ وہ ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شُدہ حکومت کے خلاف گزشتہ 20 سال سے مسلسل جارحانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ حوثی باغیوں کو ایران کی پراکسی تصوّر کیا جاتا ہے، کیوں کہ انہیں ایران کی عسکری و سیاسی حمایت حاصل ہے۔ انتہائی دُکھ کی بات ہے کہ یمن کا شمار دُنیا کے غریب ترین اسلامی ممالک میں ہوتا ہے اور اب تک ہزاروں افراد وہاں جاری خانہ جنگی کا شکار بن چُکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جنگجُو ہوش کے ناخن نہیں لیتے۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ناک اَمر یہ ہے کہ جب کوئی غیر مسلم مُلک کسی اسلامی ریاست پر حملہ کرتا ہے، تو اُمّتِ مسلمہ چیخ اُٹھتی ہے، لیکن حوثی باغیوں کو کوئی یہ بات نہیں سمجھاتا کہ وہ دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہتھیار رکھ کر اپنے مُلک کی ترقّی و خوش حالی کیلئے کردار ادا کریں اور باب المندب کو بند کرنے کی بجائے اُسے اپنے قومی مفاد کیلئے استعمال کریں، جبکہ سب سے المناک بات یہ ہے کہ حوثی باغی دُنیا بھر کے مسلمانوں کے مقدّس ترین مقامات، مکّہ مکرّمہ اور مدینہ منوّرہ تک کو میزائلز سے نشانہ بنانے سے باز نہیں آئے۔ وائے قسمت، اس سے بڑھ کر ستم ظریفی اور کیا ہوسکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حوثی باغی حملوں کیلئے جو بیلسٹک میزائلز اور ڈرون طیّارے استعمال کررہے ہیں، وہ انہیں ایران فراہم کررہا ہے۔ 2022ء میں ایک معاہدے کے تحت یمن میں جاری خانہ جنگی میں تعطّل آیا تھا لیکن اُس وقت تک 50 ہزار سے زائد یمنی اس شورش کی بھینٹ چڑھ چُکے تھے۔ بعدازاں، حالیہ ایران، امریکا جنگ کے دوران جب ایران پر امریکی فوجی اور اقتصادی دباؤ بڑھا، تو حوثیوں نے دوبارہ سعودی عرب پر حملے شروع کردیے۔ اس موقع پر حوثی باغیوں کی کوشش تھی کہ سعودی تیل باب المندب سے نہ گزرنے پائے۔ اسی دوران ''مکّہ دفاعی معاہدہ'' ہوا، جس میں پاکستان، تُرکیہ اور سعودی عرب شامل ہیں۔ اس معاہدے کی بنیادی شِق یہ ہے کہ معاہدے میں شامل کسی ایک فریق پر حملہ، تمام فریقین پر حملہ تصوّر کیا جائے گا اور حال ہی میں اِسی ایگریمنٹ کے تحت پاکستان اور تُرکیہ نے اپنی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب منتقل کی ہیں۔

دوسری جانب مشرقِ وسطیٰ میں ایران، امریکا جنگی محاذ تو فی الوقت سَرد ہے، لیکن آبنائے ہُرمز ہنوز آئل ٹینکرز اور تجارتی جہازوں کے لیے ایک خطرناک آبی گزرگاہ ہے۔ تاہم، حوصلہ افزا پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ آبنائے ہُرمز کی بندش سے قبل کی سطح پر تیل کی سپلائی شروع ہوچُکی ہے۔ یعنی یہ کہا جاسکتا ہے کہ تیل کی رسد معمول پر آنے لگی ہے۔ گرچہ وقتاً فوقتاً یہ اطلاعات سامنے آتی رہتی ہیں کہ کسی بحری جہاز یا آئل ٹینکر کو میزائل یا ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، لیکن کوئی ایسی خطرناک جنگی صُورتِ حال نہیں کہ جس کے نتائج ہلاکتوں کی صُورت میں سامنے آئیں۔ ہرچند کہ امریکا اور ایران کی جانب سے وقتاً فوقتاً ایک دوسرے کے خلاف تُند و تیز بیانات سامنے آتے رہتے ہیں لیکن یہ محض اپنے عوام کی حمایت اور ذرائع ابلاغ کی توجّہ حاصل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں، یہ خبریں بھی وقفے وقفے سے سامنے آتی رہتی ہیں کہ ثالثوں کے ذریعے مذاکرات بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہیں۔ دوسری جانب امریکا نے ایران پر بتدریج اقتصادی پابندیاں بڑھانا شروع کردی ہیں اور اب ایران کسی دوسرے مُلک میں اپنے مسافر طیّارے نہیں اُتار سکتا، جس کے نتیجے میں ایران پر معاشی دباؤ شدید تر ہوگیا ہے۔ اب نہ صرف اُسے مالیاتی دباؤ کا سامنا ہے، جس سے اُس کی کرنسی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اور ایک یو ایس ڈالر 45 لاکھ ایرانی ریال کی سطح پر پہنچ چُکا ہے، جب کہ دوسری طرف اس کی درآمدات بھی بُری طرح متاثر ہورہی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایرانی صدر، مسعود پزشکیان اور وزیرِ خارجہ، عبّاس عراقچی نے اقوامِ متّحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے ایران پر امریکی و اسرائیلی حملوں کی شدید مذمّت کی۔ نیز، انہوں نے ایران کی معاشی صُورتِ حال، ایرانی معیشت پر آبنائے ہُرمز کی بندش کے اثرات اور مذاکرات کی کوششوں پر بھی کُھل کر بات چیت کی۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ امریکا اور ایران کے مابین براہِ راست مذاکرات کے کچھ دَور بھی ہوئے لیکن پھر سفارتی محاذ پر خاموشی چھاگئی، جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ یہ مذاکرات کام یاب نہیں ہوئے۔ یادش بخیر 2013ء میں اُس وقت کے ایرانی صدر، حسن روحانی نے بھی انتہائی کشیدہ صُورتِ حال میں یو این کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران ایران کا موقف نہایت احسن انداز سے پیش کیا تھا لیکن انہوں نے ساتھ ہی سفارت کاری بھی جاری رکھی۔ انہوں نے امریکا اور دیگر فریقین سے رابطے کیے اور انہیں اعتماد میں لیا۔ حسن روحانی کی یہ کوششیں رنگ لائیں اور نتیجتاً نیوکلیئر ڈِیل ہوئی، ایران کے 40 ارب ڈالرز کے منجمد اثاثے بحال ہوئے، اسے عالمی مارکیٹ تک رسائی ملی اور ایرانی عوام نے بھی سُکھ کا سانس لیا، جب کہ دُنیا نے بھی ایٹمی معاہدے کو خوش آمدید کہا۔ بہرکیف، اس وقت ایران نے امریکا کے ساتھ معاہدے کیلئے سات شرائط پیش کی ہیں۔ دراصل، یہ وہی مطالبات ہیں، جو اسلام آباد ایم او یو اور دیگر پلیٹ فارمز پر ایران کی جانب سے پیش کیے گئے۔ لیکن امریکی صدر، ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں فوری طور پر مسترد کردیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے جنگ بندی امریکی مڈٹرم الیکشن کے بعد ہی ہوسکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کے اپنے پڑوسی ممالک پر امریکی مفادات کو نقصان پہنچانے کی آڑ میں حملوں سے خطّے میں کشیدگی نے جنم لیا اور جو عرب ممالک پہلے ایران کی حمایت کر رہے تھے، وہ بھی اس کی مذمّت کرنے لگے۔

گرچہ ایران کی جانب سے آبنائے ہُرمز بند کرنے کی حکمتِ عملی ابتدا میں خاصی موثر دکھائی دے رہی تھی لیکن آج اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ ایسے میں یہ بہتر ہوتا کہ او آئی سی کا فورم استعمال کرکے تلخی سے گریز کیا جاتا، جسے اب ختم کرنا آسان نہ ہوگا۔ جب جنگ کے بادل سَر پر منڈلا رہے ہوں، تو سفارت کاری اور مذاکرات کے آپشنز کُھلے رکھنے چاہئے۔

حالیہ دِنوں میں امریکی پالیسی میں واضح تبدیلی آئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی مجموعی فوجی حکمتِ عملی کا حصّہ تھا کہ پہلے ایران کا انفرااسٹرکچر تباہ کرے اور پھر اس پر معاشی دباؤ بڑھائے۔ تاہم، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امریکا اور اسرائیل نے ایران پر بمشکل دو ہفتے تک حملے کیے لیکن اس کے بعد ایران کی جانب سے اپنے پڑوسی عرب ممالک پر مسلسل میزائل حملے کیے جاتے رہے۔ اس وقت ایران کے خارجہ اور دفاعی پالیسی ساز اس بات پر غور کررہے ہوں گے کہ پڑوسی ممالک کو، جن سے ان کے تعلقات خاصے خوش گوار تھے، امریکی مفادات کو ہدف بنانے کی آڑ میں نشانہ بنا کر تہران کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ ایران سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک متوسّط سطح کا صنعتی مُلک ہے اور اپنی ضرورت کی اشیاء خود تیار کرتا ہے لیکن مزید امریکی پابندیوں سے اُس کی پیداوار ماضی کے مقابلے میں یقیناً کم ہوجائے گی اور اگر وہ اشیائے خورونوش، جو اُسے درآمد کرنا پڑتی ہیں، منہگی ہوں گی، تو اس کا براہِ راست اثر ایرانی عوام پر پڑے گا اور جب منہگائی بڑھے گی، تو عوام میں بےچینی پیدا ہوگی۔ ایرانی قیادت بار بار اس بات کا اعادہ کرتی رہی ہے کہ جنگ یا فوجی تصادم مسئلے کا حل نہیں بلکہ مذاکرات ہی سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے اور ایران کو یہ راستہ اُس کے دوست ممالک ہی دے سکتے ہیں۔ آج ایران کی زیادہ تر ملیشیاز غیر موثر ہوچُکی ہیں اور اس لیے پڑوسی عرب ممالک کے لیے بھی خطرات کم ہوگئے ہیں۔ اِسی طرح جب ایرانی درآمدات کم ہوں گی، تو اس کے ہتھیاروں کی تیاری کے عمل پر بھی منفی اثرات مرتّب ہوں گے۔ اُدھر امریکا کو بھی اندازہ ہے کہ وہ غیر معیّنہ مدّت تک ایران کے خلاف محاذ آرائی جاری نہیں رکھ سکتا، کیوں کہ اوّل تو اس کے عوام کو اس جنگ سے کوئی دِلچسپی نہیں اور پھر بار بار تیل اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے صدر ٹرمپ کی مقبولیت کم ہورہی ہے۔ امریکا ایک جمہوری مُلک ہے اور وہاں اگلے ماہ وسط مدّتی انتخابات ہورہے ہیں اور اس کے نتائج اس جنگ پر اثرانداز ہوسکتے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کو بھی اُمید ہے کہ مڈٹرم الیکشن میں ٹرمپ کی کامیابی یا ناکامی کا اثر اس جنگ کے خاتمہ یا کسی معاہدے تک پہنچنے میں مدد دے گا لیکن اس کا فیصلہ امریکی عوام نے کرنا ہے۔ لہٰذا، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ تصادم کی بجائے مذاکرات کا راستہ اپنایا جائے اور ایرانی صدر کو اپنے دورہ امریکا سے بھی اس بات کا اندازہ ہوگیا ہوگا اور یقیناً اُنہوں نے اپنے خیالات ایران کے طاقت وَر حلقوں تک بھی پہنچادیے ہوں گے۔ اُدھر دُنیا میں کئی اہم ممالک میں سیاسی تبدیلیاں رُونما ہو رہی ہیں، بالخصوص یورپ میں تبدیلی واضح دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ عرصے قبل برطانیہ کے لوکل باڈیز الیکشن میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد وزیرِ اعظم، کیئر اسٹارمر کو مستعفی ہونا پڑا۔ ان انتخابات میں دائیں بازو کی جماعت نے، جو کہ تارکینِ وطن کی مخالف ہے، لیبر پارٹی کو عبرت ناک شکست دی اور اس وقت بھی ''دی نیشن پارٹی'' کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ہم گزشتہ کئی برسوں سے اس بات پر توجّہ مبذول کروا رہے ہیں کہ یورپ میں قوم پرستی کی لہر مسلسل زور پکڑتی جارہی ہے جبکہ جرمنی کے ریاستی انتخابات میں بھی برطانیہ جیسی صُورتِ حال دیکھی گئی۔ اس کی کئی اہم ریاستوں میں حُکم راں جماعت، ڈیموکریٹک پارٹی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور قوم پرست پارٹی، اے ایف ڈی یعنی ''آلٹرنیٹو فار جرمنی'' نے اکثریت حاصل کی۔ یہ شکست اتنی غیر متوقّع اور غیر معمولی تھی کہ موجودہ جرمن چانسلر اور ''جے ڈی پی پارٹی'' کے سربراہ، فریڈرک مرز کو شکست کے فوراً بعد یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ان کی پارٹی کو تباہ کُن صُورتِ حال کا سامنا ہے۔ گو کہ ان انتخابات میں اے ایف ڈی مکمل اکثریت حاصل نہ کرسکی، لیکن نتائج مستقبل کا احوال بتارہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قوم پرست جماعت نے بعض ریاستوں میں واضح اکثریت حاصل کی ہے، اصل چیلنج یہ ہے کہ وہ جرمنی کے عام انتخابات میں بھی اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اے ایف ڈی ایک پاپولسٹ پارٹی ہے اور اس کے منشور کے بنیادی نکات میں تارکینِ وطن پر پابندی اور عوام پر منہگائی کے منفی اثرات کا سدِباب شامل ہے۔ یاد رہے کہ اے ایف ڈی نے مشرقی جرمنی کی ریاستوں میں اکثریت حاصل کی ہے، جو انضمام سے قبل بھی سوویت یونین کے زیرِ اثر ہونے کی وجہ سے قوم پرستانہ نظریات رکھتا تھا۔ یہ بھی واضح رہے کہ جرمنی کی دوسری بڑی سیاسی جماعتیں اے ایف ڈی کے قوم پرستانہ نظریات ہی کی وجہ سے حکومت بنانے کیلئے اس سے اتحاد نہیں کرتیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جرمنی کے ان انتخابی نتائج کے یورپ پر کیا اثرات مرتّب ہوسکتے ہیں؟ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے اور ماضی میں اِس کا شمار یورپ کے طاقت وَر ترین ممالک میں ہوتا رہا ہے۔ اگر یورپ کی موجودہ صُورتِ حال پر نظر ڈالی جائے، تو یہاں بہت سے ممالک میں دائیں بازو کی قوم پرست جماعتیں اقتدار میں آچُکی ہیں۔

ان میں اٹلی، آسٹریا، ہالینڈ اور ہنگری قابلِ ذکر ہیں، جب کہ فرانس جیسے روایت پسند مُلک میں بھی قوم پرست ''نیشنل ریلی پارٹی'' مقبولیت حاصل کررہی ہے، جب کہ ماہرین کی رائے ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آسکتی ہے۔ گرچہ یورپ میں قوم پرست جماعتوں کی مقبولیت سے وہاں جمہوریت فوراً ختم نہیں ہوجائے گی۔ تاہم، بڑی جماعتوں کو اپنی ہر شکست کے بعد اپنی پالیسی پر نظرِ ثانی کرنا پڑے گی۔ چونکہ قوم پرست جماعتوں کے ایجنڈے میں تارکینِ وطن کا انخلاء سرِ فہرست ہے، لہٰذا مستقبل میں تارکینِ وطن کیلئے مشکلات پیدا ہوں گی، جیسا کہ اِن دنوں امریکا میں انہیں سامنا کرنا پڑرہا ہے۔ علاوہ ازیں، یوکرین جنگ نے بھی جرمنی کی سیاست پر گہرے اثرات مرتّب کیے ہیں۔ آج جرمنی معاشی طور پر اپنی سابقہ پوزیشن بحال کرنے کی جدوجہد کررہا ہے کہ یوکرین جنگ سے منہگائی میں اضافے کے سبب عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہوگئی ہے، جس سے اے ڈی ایف جیسی قوم پرست جماعتیں فائدہ اُٹھا رہی ہیں اور یہی منشور یورپ میں بھی بائیں بازو کی جماعتوں کو اقتدار میں لانے میں مددفراہم کررہا ہے۔ پہلے یہ جماعتیں مزدور ووٹرز کے ذریعے کام یابی حاصل کرتی تھیں لیکن اب عام شہری خود میدان میں آگیا ہے اور اُس کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ جرمنی سمیت یورپ کی دیگر بڑی سیاسی جماعتوں کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی روایتی حکمتِ عملی، جدید معاشی تقاضوں سے ہم آہنگ کریں کہ مستقبل میں ان کی مقبولیت کی برقراری کا دارومدار اِسی بات پر ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کو کس حد تک مطمئن کرنے میں کام یاب ہوتی ہیں۔

آسمان کے بعد خلا بھی میدانِ جنگ؟

آوازِ تسنیم:

انسان نے جب پہلی مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا تو وہاں اسے سورج، چاند، ستارے اور ایک ایسی خاموش وسعت دکھائی دی جس کے سامنے اس کی اپنی دنیا نہایت مختصر محسوس ہوتی تھی۔ صدیوں تک خلا انسان کے لیے حیرت، جستجو، عبادت اور تخیل کا میدان رہا، لیکن گزشتہ ایک صدی میں سائنس نے اس خاموش وسعت کو انسانی سرگرمیوں کا حصہ بنا دیا۔ مصنوعی سیارے زمین کے گرد گردش کرنے لگے، مواصلات براعظموں سے نکل کر مداروں تک پہنچ گئے، عالمی سمت یابی کا نظام انسانی زندگی کا روزمرہ حصہ بن گیا، موسم کی پیش گوئی سے لے کر بینکاری، انٹرنیٹ، ٹیلی مواصلات، سمندری سفر، فضائی آمدورفت اور فوجی نگرانی تک بےشمار شعبے خلا پر منحصر ہوگئے۔ اب وہی خلا، جسے کبھی انسان نے جنگوں سے بالاتر ایک مشترکہ میراث سمجھا تھا، عالمی طاقتوں کی نئی عسکری مسابقت کا مرکز بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ 14 ستمبر 2026 کو امریکا کے فضائیہ کے سیکریٹری ٹرائے مینک نے اعلان کیا کہ امریکی خلائی فورس کے پاس زمین کے مدار میں ''خلائی کنٹرول کے ہتھیار'' موجود ہیں جو مشترکہ امریکی افواج کو دشمن کی کارروائیوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس اعلان کی غیر معمولی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے جب امریکی حکومت کے کسی اعلیٰ عہدے دار نے علانیہ طور پر تسلیم کیا ہے کہ امریکہ کے پاس مدار میں تعینات خلائی ہتھیار موجود ہیں۔ تاہم مینک نے ان ہتھیاروں کی نوعیت، تعداد، مخصوص مدار، تعیناتی کی تاریخ یا عملی صلاحیت کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی۔ یہاں خبر کے الفاظ سے زیادہ اہم اس کے پیچھے چھپا ہوا تصور ہے ''خلائی کنٹرول۔'' عام قاری کے لیے ہتھیار کا تصور عموماً میزائل، توپ، بم یا بندوق سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن خلا میں جنگی طاقت کی صورتیں کہیں زیادہ پیچیدہ ہوسکتی ہیں۔ کسی مصنوعی سیارے کو جسمانی طور پر تباہ کرنا ایک طریقہ ہے، مگر اسے تباہ کیے بغیر اس کے رابطے میں خلل ڈالنا، اس کے سگنل کو جام کرنا، اس کی معلوماتی صلاحیت کو متاثر کرنا، اس کے نظام میں سائبر مداخلت کرنا، اس کے قریب جا کر اس کی سرگرمی کو محدود کرنا یا کسی مخصوص مدار میں اس کی نقل و حرکت پر اثرانداز ہونا بھی ''خلائی کنٹرول'' کے دائرے میں آسکتا ہے۔ اسی لیے موجودہ اعلان سے یہ نتیجہ نکالنا قبل از وقت ہوگا کہ امریکہ نے مدار میں لازماً ایسا ہتھیار رکھا ہے جو دوسرے سیارچے کو میزائل سے تباہ کرتا ہے۔ بعض ماہرین نے امکان ظاہر کیا ہے کہ اس نوعیت کے نظام غیر حرکی، مثلاً برقی جنگ یا دوسرے طریقوں پر مبنی ہوسکتے ہیں، مگر امریکی حکومت نے اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی۔ اس فرق کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ خلا میں جنگ صرف ''کسی چیز کو تباہ کرنے'' کا نام نہیں۔ جدید جنگی طاقت کا ایک بڑا حصہ اس معلومات پر منحصر ہے جو مصنوعی سیارے فراہم کرتے ہیں۔ زمین پر موجود فوجی دستے اگر یہ جانتے ہوں کہ دشمن کے میزائل کہاں ہیں، بحری جہاز کس سمت بڑھ رہے ہیں، فوجی دستے کس مقام پر جمع ہورہے ہیں اور کس علاقے میں موسم کیسا ہے تو ان کی فیصلہ سازی کہیں زیادہ موثر ہوجاتی ہے۔ عالمی سمت یابی اور درست وقت کے نظام کے بغیر جدید میزائل، ڈرون، طیارے، بحری جہاز اور فوجی مواصلاتی نظام اپنی بہت سی صلاحیت کھو سکتے ہیں۔ یوکرین کی جنگ نے بھی دکھایا ہے کہ تجارتی اور مواصلاتی خلائی نظام کس طرح زمینی جنگی کارروائیوں میں فیصلہ کن کردار ادا کرسکتے ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق تجارتی مصنوعی سیاروی نظام نے یوکرین کو مواصلات، ڈرونوں کی رہنمائی اور حقیقی وقت کی معلومات میں اہم مدد فراہم کی۔ اس لیے آج مصنوعی سیارہ محض آسمان میں گردش کرتا ہوا ایک سائنسی آلہ نہیں رہا۔ وہ کسی ریاست کی آنکھ بھی ہوسکتا ہے، کان بھی، مواصلاتی مرکز بھی، سمت یابی کا ذریعہ بھی اور فوجی کمان کے پورے نظام کا ایک اہم حصہ بھی۔ اگر دشمن کسی ملک کے مصنوعی سیاروں کو ناکارہ بنادے تو ضروری نہیں کہ زمین پر ایک بھی میزائل داغا جائے، مگر اس ریاست کی جنگی صلاحیت شدید متاثر ہوسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، چین اور روس کے درمیان خلائی مقابلہ صرف نئے راکٹ بنانے کا مقابلہ نہیں بلکہ اس بات کا مقابلہ بھی ہے کہ جنگ کی صورت میں کون اپنی خلائی آنکھیں کھلی رکھ سکتا ہے اور کون مخالف کی آنکھیں بند کرسکتا ہے۔ امریکی حکام کئی برس سے خبردار کرتے رہے ہیں کہ چین اور روس ایسی صلاحیتیں ترقی دے رہے ہیں جو امریکی اور اتحادی مصنوعی سیاروں کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ امریکی خلائی کمان نے مختلف مواقع پر کہا ہے کہ روس اور چین کے پاس برقی خلل، مواصلاتی اور عالمی سمت یابی کے سگنل میں مداخلت، سائبر حملوں، زمین سے داغے جانے والے مخالفِ مصنوعی سیارہ نظام اور مدار میں موجود دیگر خلائی اجسام کے ذریعے مداخلت جیسی صلاحیتیں موجود یا زیرِ ترقی ہیں۔ امریکی خلائی فورس بھی اپنی سرکاری دستاویزات میں کہتی ہے کہ چین اور روس خلائی اور مخالفِ خلائی صلاحیتیں تیار کررہے ہیں جن کا مقصد امریکی خلائی خدمات کو متاثر یا محدود کرنا ہوسکتا ہے۔ یہاں ایک نہایت اہم سائنسی حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ خلا میں موجود کسی مصنوعی سیارے کو تباہ کرنا زمین پر کسی عمارت کو تباہ کرنے سے بالکل مختلف ہے۔ زمین پر عمارت کے ملبے کا زیادہ تر حصہ زمین ہی پر رہتا ہے، مگر مدار میں تباہ کیا جانے والا مصنوعی سیارہ ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہوسکتا ہے۔ یہ ٹکڑے بھی اسی رفتار سے مدار میں گردش کرتے رہتے ہیں اور دوسرے مصنوعی سیاروں، خلائی اسٹیشنوں اور مستقبل کے خلائی مشنوں کے لیے خطرناک بن سکتے ہیں۔ 2007 میں چین کے ایک مخالفِ مصنوعی سیارہ تجربے اور 2021 میں روسی تجربے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ملبے نے اس خطرے کو نمایاں کیا۔ اسی پس منظر میں امریکہ نے 2022 میں اعلان کیا تھا کہ وہ تباہ کن براہِ راست داغے جانے والے مخالفِ مصنوعی سیارہ میزائل تجربات نہیں کرے گا۔ ناسا نے بھی خبردار کیا تھا کہ ایسے تجربات زمین کے نچلے مدار میں موجود مصنوعی سیاروں اور انسانی خلائی پروازوں کے لیے سنگین خطرہ پیدا کرسکتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف امریکا، چین یا روس کا نہیں۔ خلا میں پیدا ہونے والا ملبہ کسی قومی سرحد کو نہیں پہچانتا۔ اگر ایک ریاست کسی دوسرے ملک کے مصنوعی سیارے کو تباہ کرکے ہزاروں ٹکڑے مدار میں چھوڑ دے تو ان میں سے کوئی ٹکڑا تیسرے ملک کے مصنوعی سیارے سے بھی ٹکرا سکتا ہے۔ اس طرح ایک جنگی اقدام کا اثر اس ریاست سے کہیں آگے پہنچ سکتا ہے جس کے خلاف وہ کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خلائی سلامتی کا سوال دراصل عالمی سلامتی کا سوال ہے۔ لیکن موجودہ امریکی اعلان کی سب سے گہری معنویت اس کے عسکری پہلو سے بھی آگے ہے۔ یہ دراصل اس بات کا اعتراف ہے کہ خلائی طاقت اب قومی طاقت کا باقاعدہ حصہ بن چکی ہے۔ 2019 میں قائم کی جانے والی امریکی خلائی فورس اسی تبدیلی کی علامت ہے۔ کبھی فضائی طاقت کو جنگ کا فیصلہ کن نیا میدان سمجھا جاتا تھا؛ پھر سمندر اور فضا کے ساتھ سائبر دنیا ایک نیا محاذ بنی؛ اب خلا بھی عملی طور پر اس عالمی عسکری تصور کا حصہ بن چکا ہے جس میں ریاستیں زمین سے اوپر موجود انفرااسٹرکچر کو اپنے دفاع اور طاقت کے لیے بنیادی حیثیت دیتی ہیں۔ یہ تبدیلی صرف عسکری اداروں کی خواہش کا نتیجہ نہیں بلکہ جدید تہذیب کی اپنی ساخت کا منطقی نتیجہ بھی ہے۔

جب ہماری معیشت، مواصلات، بینکاری، موسمیاتی نگرانی، فضائی سفر، سمندری تجارت اور فوجی کمان مصنوعی سیاروں پر انحصار کرنے لگیں تو ان سیاروں کا تحفظ قومی سلامتی کا لازمی جزو بن جاتا ہے۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ''تحفظ'' اور ''غلبہ'' کے درمیان لکیر دھندلی ہونے لگتی ہے۔ ایک ریاست کہتی ہے کہ اسے اپنے مصنوعی سیارے بچانے کیلئے ہتھیار چاہیے۔ دوسری ریاست اسے اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ کر جوابی ہتھیار تیار کرتی ہے؛ پہلی ریاست پھر اپنی دفاعی صلاحیت بڑھاتی ہے؛ یوں دفاعی منطق رفتہ رفتہ عسکری دوڑ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ خلا میں یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ زمین پر فوجی طاقت کے مقابلے کے باوجود سرحدیں، جغرافیہ اور فاصلے ایک خاص حد تک خطرات کو محدود کرتے ہیں؛ خلا میں ایسا نہیں۔ ایک مصنوعی سیارہ زمین کے گرد انتہائی تیز رفتاری سے گردش کرتا ہے اور اس کا مدار ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر موجود دیگر خلائی نظاموں کے ساتھ ایک پیچیدہ تعلق رکھتا ہے۔ یہاں کسی غلط فہمی، غلط حساب یا غیر متوقع مداخلت کے نتائج بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ٹرائے مینک کا اعلان محض ایک فوجی بیان نہیں بلکہ آنے والے زمانے کی ایک علامت ہے۔ انسان نے خلا کو فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا، مگر اب سوال یہ ہے کہ کہیں وہ اسے تقسیم کرنے کی کوشش تو نہیں کررہا؟ یہ سوال اس وقت مزید اہم ہوجاتا ہے جب امریکا پہلی مرتبہ کھلے الفاظ میں تسلیم کرتا ہے کہ اس کے پاس مدار میں ''خلائی کنٹرول کے ہتھیار'' موجود ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا مقصد دشمن کی کارروائیوں سے امریکی افواج کا دفاع ہے۔ بظاہر یہ ایک دفاعی دلیل ہے، لیکن عالمی سیاست میں دفاعی صلاحیت اور جارحانہ صلاحیت کے درمیان فرق ہمیشہ اتنا واضح نہیں رہتا۔ جس ہتھیار کو ایک ریاست دفاع کیلئے ضروری سمجھتی ہے، وہی ہتھیار دوسری ریاست کی نظر میں پہلے حملے کی صلاحیت ہوسکتا ہے۔ اسی لیے خلا میں طاقت کا توازن روایتی جوہری توازن سے مختلف مگر اس سے کم خطرناک نہیں ہوسکتا۔ جوہری ہتھیاروں میں بنیادی خوف یہ تھا کہ ایک غلط قدم پوری انسانیت کیلئے تباہ کن ہوسکتا ہے۔ خلائی جنگ میں خطرہ شاید مختلف شکل اختیار کرے: مصنوعی سیاروں کی بڑے پیمانے پر تباہی، مواصلاتی نظام کا تعطل، عالمی سمت یابی میں خلل، موسم کی نگرانی کے نظام کی ناکامی، مالیاتی نیٹ ورک پر اثرات اور زمین کے نچلے مدار میں خطرناک خلائی ملبے کا پھیلاو۔ یہ سب براہِ راست ایٹمی دھماکے کے مترادف نہیں، مگر جدید تہذیب کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

قانونی اعتبار سے صورتِ حال بھی نہایت دلچسپ ہے۔ 1967 کا بیرونی خلا معاہدہ جوہری ہتھیاروں اور دیگر تباہی پھیلانے والے وسیع پیمانے کے ہتھیاروں کو زمین کے مدار میں رکھنے یا خلا میں کسی اور طریقے سے نصب کرنے سے روکتا ہے۔ چاند اور دیگر اجرامِ فلکی پر فوجی اڈے، قلعہ بندی، ہتھیاروں کے تجربات اور فوجی مشقوں پر بھی پابندیاں عائد کرتا ہے۔ لیکن معاہدہ ہر قسم کے روایتی ہتھیار کو مدار میں رکھنے پر عمومی پابندی عائد نہیں کرتا۔ یہی قانونی خلا موجودہ خلائی عسکری مسابقت کے لیے ایک بنیادی مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ فرق نہایت اہم ہے۔ اگر مدار میں موجود امریکی نظام جوہری یا بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار نہیں تو محض ان کا خلا میں موجود ہونا لازماً 1967 کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں بنتا۔ لیکن قانونی طور پر ممکن ہونا اخلاقی طور پر دانش مندانہ ہونے کی ضمانت نہیں۔ تاریخ میں کئی ایسی ٹیکنالوجیاں موجود ہیں جو قانونی تھیں مگر ان کے پھیلاو نے عالمی خطرات بڑھا دیے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا عالمی برادری خلا میں ایسے واضح قواعد بنا سکتی ہے جن کے ذریعے دفاعی ضرورت اور تباہ کن عسکری دوڑ کے درمیان حد قائم کی جاسکے؟ چین اور روس پہلے ہی امریکہ کی خلائی پالیسی پر شدید تشویش ظاہر کرتے رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے حالیہ برسوں میں خلا میں ہتھیاروں کی دوڑ روکنے کے لیے قانونی طور پر پابند معاہدے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے خلائی عسکری پروگراموں کو عالمی تزویراتی استحکام کیلئے خطرہ قرار دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ اگر ایک بڑی طاقت مدار میں مداخلت یا روک تھام کی صلاحیتیں تعینات کرتی ہے تو دوسری طاقتیں خاموش نہیں رہیں گی۔ یہیں سے ''تھالی میں رکھے ہوئے دفاع'' کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک ریاست کے پاس ایسا مصنوعی سیارہ موجود ہے جو دشمن کے مصنوعی سیارے کو جام کرسکتا ہے۔ دوسری ریاست اس خطرے کو محسوس کرکے اسی نوعیت کا نظام تیار کرتی ہے۔ پہلی ریاست پھر زیادہ طاقتور نظام بناتی ہے۔ دوسری ریاست اپنے سیاروں کو زیادہ محفوظ بنانے کے لیے مزید مصنوعی سیارے بھیجتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں طرف دفاعی اقدامات کا مجموعہ ایک نئی خلائی اسلحہ دوڑ میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ خلائی جنگ کی سب سے خطرناک شکل شاید وہ نہیں ہوگی جس میں میزائل ایک دوسرے کو تباہ کریں؛ ممکن ہے زیادہ خطرناک وہ جنگ ہو جس میں کوئی فریق دشمن کے مصنوعی سیارے کو خاموش کردے اور اسے تباہ بھی نہ کرے۔ اس صورت میں ملبہ پیدا نہیں ہوگا، حملہ بظاہر محدود ہوگا اور اس کا ذمہ دار متعین کرنا بھی مشکل ہوسکتا ہے۔ برقی خلل، سائبر حملہ، قریب جا کر مداخلت یا سگنل میں تبدیلی ایسی صلاحیتیں ہیں جو جنگ کو ''نظر نہ آنے والی جنگ'' بنا سکتی ہیں۔ امریکی اور اتحادی حکام پہلے ہی چین اور روس کی مختلف مخالفِ خلائی صلاحیتوں، بشمول برقی خلل، سائبر حملوں، براہِ راست مخالفِ مصنوعی سیارہ نظام اور مدار میں قریب جا کر کارروائی کرنے والی صلاحیتوں کے بارے میں خدشات ظاہر کرچکے ہیں۔ اس نئے منظرنامے میں مصنوعی ذہانت بھی فیصلہ کن کردار ادا کرسکتی ہے۔ مدار میں ہزاروں مصنوعی سیارے اور خلائی اجسام موجود ہوں تو انسان کیلئے ہر لمحے ان کی نقل و حرکت کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں۔ مصنوعی ذہانت ایسے نظاموں کو ترتیب دے سکتی ہے جو غیر معمولی حرکت کی نشاندہی کریں، کسی دوسرے خلائی جسم کے قریب آنے کا اندازہ لگائیں اور ممکنہ خطرے کی پیش گوئی کریں۔ لیکن یہی صلاحیت ایک نئے خطرے کو بھی جنم دیتی ہے۔ اگر مصنوعی ذہانت نے کسی معمول کی خلائی سرگرمی کو دشمنی سمجھ لیا تو کیا ہوگا؟ اگر خودکار نظام نے چند سیکنڈ میں دفاعی کارروائی کا فیصلہ کرلیا تو انسانی تصدیق کا وقت کہاں بچے گا؟

یہ سوال زمین پر موجود میزائل دفاع سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوسکتا ہے کیونکہ خلا میں فاصلے، رفتار اور وقت کا تعلق مختلف نوعیت کا ہے۔ ایک خلائی جسم ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرسکتا ہے۔ چند منٹوں میں اس کی پوزیشن تبدیل ہوجاتی ہے۔ اگر فیصلہ سازی مکمل طور پر خودکار کردی جائے تو غلط فہمی اور غلط شناخت کا خطرہ ایک نئے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے مستقبل کی خلائی سلامتی کا اصل چیلنج صرف یہ نہیں کہ کون زیادہ طاقتور ہتھیار بناتا ہے۔ اصل چیلنج یہ ہوگا کہ کون ایسی طاقت کے ساتھ زیادہ ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ طاقت کا توازن ضروری ہوسکتا ہے، لیکن طاقت کے استعمال کے قواعد اس سے بھی زیادہ ضروری ہیں۔ امریکا کی موجودہ پالیسی میں ایک دل چسپ تضاد بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایک طرف وہ تباہ کن براہِ راست مخالفِ مصنوعی سیارہ میزائل تجربات سے اجتناب کی پالیسی کی حمایت کرچکا ہے، کیوں کہ ایسے تجربات خطرناک خلائی ملبہ پیدا کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اب مدار میں خلائی کنٹرول کے ہتھیاروں کی موجودگی کا اعتراف کررہا ہے۔ اس تضاد کو سمجھنے کیلئے ''تباہی'' اور ''خلائی کنٹرول'' کے درمیان فرق سمجھنا ہوگا۔ ممکن ہے مستقبل کی جنگی حکمت عملی ایسی صلاحیتوں کی طرف جائے جو دشمن کے مصنوعی سیارے کو مستقل طور پر تباہ کرنے کے بجائے عارضی طور پر ناکارہ یا محدود کردیں، تاکہ ملبہ کم پیدا ہو۔ لیکن ایسی صلاحیت بھی اگر جنگ کے دوران استعمال ہو تو عالمی خلائی نظام کے لیے شدید خطرہ بن سکتی ہے۔ یہاں انسانیت کے لیے ایک بنیادی سوال ابھرتا ہے: کیا خلا کو بھی زمین کی طرح طاقت کے مقابلے کا میدان بننا چاہیے؟ شاید حقیقت یہ ہے کہ خلا پہلے ہی اس سمت بڑھ چکا ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ نہیں کہ اسے عسکری مقابلے سے کیسے مکمل طور پر محفوظ رکھا جائے، بلکہ یہ ہے کہ اس مقابلے کو کس طرح ایسے قواعد کے اندر رکھا جائے جو انسانی تہذیب کے مشترکہ مفادات کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خلا صرف فوجوں کا نہیں۔ وہاں موسمیاتی مصنوعی سیارے ہیں، سائنسی مشاہدہ گاہیں ہیں، مواصلاتی نظام ہیں، تجارتی مصنوعی سیارے ہیں اور ایسے بےشمار نظام ہیں جن سے دنیا کی عام شہری زندگی وابستہ ہے۔ اگر خلائی جنگ بڑھی تو اس کے اثرات صرف واشنگٹن، بیجنگ یا ماسکو تک محدود نہیں رہیں گے۔ کئی ممالک مواصلات، موسم، عالمی سمت یابی، فضائی و بحری تجارت اور اطلاعاتی نظام کے ذریعے اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ اسی لیے خلا کی عسکری دوڑ کو محض بڑی طاقتوں کا مسئلہ سمجھنا خطرناک ہوگا۔ جس طرح زمین کا ماحول کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں، اسی طرح خلائی ماحول بھی کسی ایک طاقت کا نجی میدان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ملک کا پیدا کیا ہوا خلائی ملبہ دوسرے ملک کے مصنوعی سیارے کو تباہ کرسکتا ہے۔ ایک طاقت کا برقی خلل کسی دوسری ریاست کی مواصلاتی خدمات کو متاثر کرسکتا ہے؛ ایک خلائی جنگ کا نتیجہ دنیا کے ایسے حصوں تک پہنچ سکتا ہے جہاں جنگ کے فیصلے میں ان کا کوئی کردار ہی نہ ہو۔ ٹرائے مینک نے امریکی اعلان کو دفاع اور بازداریت کے تناظر میں پیش کیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ بدلتے ہوئے خطرات کے ماحول میں امریکہ کو اپنی افواج کو محفوظ رکھنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اعلان میں الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ لیکن تاریخ کا سبق یہ ہے کہ بازداریت اور اسلحہ دوڑ کے درمیان فاصلہ کبھی کبھی بہت کم رہ جاتا ہے۔ ایک فریق کا ''دفاع'' دوسرے فریق کیلئے ''حملے کی تیاری'' محسوس ہوسکتا ہے۔ یہی غلط فہمی جنگوں کو جنم دیتی ہے۔ خلا میں یہ خطرہ اس لیے زیادہ سنگین ہے کہ وہاں ہونے والی کارروائیوں کا براہِ راست مشاہدہ مشکل ہوسکتا ہے، ارادوں کا اندازہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا اور فیصلہ سازی کے لیے وقت کم ہوسکتا ہے۔

لہٰذا دنیا کو ایک ایسے نئے خلائی معاہدے کی ضرورت ہے جو صرف جوہری ہتھیاروں تک محدود نہ ہو بلکہ مدار میں تعینات روایتی خلائی ہتھیاروں، مخالفِ مصنوعی سیارہ کارروائیوں، خطرناک قریب المداری سرگرمیوں، سائبر اور برقی حملوں، خلائی ملبے اور خودکار جنگی نظاموں کے استعمال کے واضح اصول وضع کرے۔ اقوامِ متحدہ کے پلیٹ فارم پر بھی خلائی اسلحہ کی دوڑ روکنے اور غلط فہمی و غلط حساب سے پیدا ہونے والے خطرات کم کرنے کیلئے موثر بین الاقوامی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ انسان نے چاند پر قدم رکھنے کے بعد یہ سمجھا تھا کہ خلا اسے اپنی حدود سے آزاد کرے گا۔ مگر اب خدشہ یہ ہے کہ زمین کی سیاسی رقابتیں خلا تک پہنچ کر اس نئی دنیا کو بھی طاقت کے تنازع میں تبدیل نہ کردیں۔ آسمان کے بعد خلا بھی اگر میدانِ جنگ بن گیا تو انسان اپنی جنگوں کو صرف زمین سے اوپر منتقل کرے گا، ختم نہیں کرے گا۔ امریکہ کا تازہ اعتراف اسی لیے ایک خبر سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اس دور کی دستک ہے جس میں جنگی طاقت کی تعریف زمین سے نکل کر مدار تک پہنچ رہی ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ خلا میں ہتھیار ہوسکتے ہیں یا نہیں؛ سوال یہ ہے کہ ان ہتھیاروں کے ہوتے ہوئے انسانیت اپنے مشترکہ خلائی ماحول کو کس طرح محفوظ رکھے گی۔ شاید آنے والی صدیوں کے مورخ جب ہماری تہذیب کو دیکھیں گے تو وہ یہ نہیں لکھیں گے کہ انسان نے خلا میں کتنے سیارے بھیجے تھے۔ وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب انسان نے خلا تک اپنی طاقت پہنچا دی تھی تو کیا اس نے اپنی عقل، ذمہ داری اور اخلاقیات کو بھی وہاں تک پہنچایا تھا یا نہیں۔ کیوں کہ خلا فتح کرنے سے زیادہ مشکل کام شاید اسے جنگ سے بچانا ہوگا۔ اور اگر انسان اس امتحان میں ناکام ہوا تو ممکن ہے زمین پر رہنے والے اربوں انسانوں کو یہ احساس بہت دیر سے ہو کہ انہوں نے جنگ کا میدان آسمان تک پہنچا دیا ہے، مگر اس جنگ سے بچنے کی کوئی دوسری زمین ان کے پاس موجود نہیں۔

☆☆☆

पानी बचाना अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी

पूरन चंद सरीन

बारिश की अनिश्चितता, भूजल का अंधाधुंध दोहन और जलस्रोतों पर अतिक्रमण ने पानी के संकट को गंभीर बना दिया है। सवाल केवल पानी की उपलब्धता का नहीं, बल्कि उसे बचाने और न्यायपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी का भी है। नीति आयोग ने 2018 में अनुमान लगाया था कि 2030 तक भारत में पानी की जितनी खपत होगी, वह तब उपलब्ध पानी से दोगुनी होगी। यह उस समय का पूर्वानुमान था, आज की स्थिति का माप नहीं लेकिन चिंता अभी से करनी होगी क्योंकि जल संरक्षण की जरूरत को समझने के लिए यह पर्याप्त चेतावनी है। पानी की एक-एक बूंद बचाने की अपील की जाती है तो यह सवाल उठना ही चाहिए कि पानी बर्बाद करने की कीमत आखिर कौन चुकाता है और उसकी वसूली किससे होती है? विकास के नाम पर कहीं तालाब पाटकर इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं, कहीं बरसाती नालों के रास्ते पर बस्तियां बस जाती हैं और कहीं जमीन में पानी पहुंचाने वाली खुली जगहों पर कंक्रीट बिछा दिया जाता है। फिर बारिश में शहर डूबते हैं और गर्मी में पानी की किल्लत। ऐसे विकास की कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़ेगी, यह स्पष्ट है। जल आंदोलन की शुरुआत अपने घर से : एक टैलीविजन कार्यक्रम में एक प्रसिद्ध अभिनेता ने मजाक में बताया कि उनकी पत्नी तब तक नहाती रहती है, जब तक सोसाइटी के दूसरे निवासियों के घरों में पानी आना बंद न हो जाए और वे शिकायत करने न पहुंच जाएं। बात हंसी-मजाक में कही गई होगी लेकिन इसके पीछे छिपी मानसिकता पर विचार जरूरी है। घंटों शॉवर के नीचे बैठे रहना, गाडियों को लगातार बहते पानी से धोना, हाथ धोते समय नल खुला छोडना और टंकी भरने के बाद भी पानी बहने देना, ये ऐसी आदतें हैं, जिन्हें हमने सामान्य मान लिया है। दलील दी जाती है कि पानी का बिल भरते हैं, जितना चाहे इस्तेमाल करें। सरकारी आपूर्ति कम हो तो मोटर लगाकर भूजल निकाल लेते हैं। सार्वजनिक नलों से पानी बहता रहता है और पाइपलाइनें रिसती रहती हैं। दूसरी ओर लाखों घरों की महिलाएं सुबह उठकर सोचती हैं कि आज नल से पानी आएगा या टैंकर के भरोसे रहना पड़ेगा। किसान आसमान की ओर देखकर फसल का भविष्य तलाशता है और शहर का परिवार पीने का साफ पानी खरीदने को मजबूर है। किसी के लिए पानी सुविधा है, तो किसी के लिए रोज का संघर्ष। संकट बढने पर पानी बेचने वालों की चांदी है। जीवन की बुनियादी सुविधा मुनाफे का साधन है। प्रश्न उठता है कि जल संरक्षण केवल व्यक्तिगत सदाचार है या सामाजिक न्याय और क्या किसी को भी यह अधिकार है कि वह जल बर्बाद करे, जबकि इसकी एक बूंद जीवन बचा सकती है?

आज का कार्टून

जानलेवा होती हवा: सर्दियों से पहले ही प्रदूषण की चुनौती

"प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। नागरिकों को निजी वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जा की बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता एवं हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों में भाग लेना भी आवश्यक है। मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को जनजागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि स्वच्छ हवा का महत्व केवल प्रदूषण के चरम पर ही याद न आए। साथ ही, वायु गुणवत्ता के आंकड़े पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक किए जाएं और नागरिकों को प्रदूषण के स्तर के अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाए। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें, उद्योग, किसान और नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटें।"

ललित गर्ग

सर्दियों ने अभी पूरी तरह दस्तक भी नहीं दी है कि देश के अनेक शहरों की हवा में प्रदूषण का जहर घुलने लगा है। दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता का तेजी से बिगड़ना इस बात का संकेत है कि प्रदूषण का संकट अब केवल सर्दियों की मौसमी समस्या नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन, शहरी विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने खड़ी एक गंभीर चुनौती बन चुका है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में दमघोंटू धुंध, आंखों में जलन, सांस लेने में कठिनाई और अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की संख्या के साथ यह संकट सामने आता है। विडंबना यह है कि समस्या के कारणों की पहचान होने और उपायों की जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद हम हर वर्ष उसी त्रासदी को दोहराने के लिए विवश दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि क्या स्वच्छ हवा में सांस लेना भी अब नागरिकों के लिए एक दुर्लभ सुविधा बनकर रह जाएगा? वायु प्रदूषण किसी एक कारण या किसी एक राज्य की देन नहीं है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, सड़कों पर जमा मिट्टी, कचरा और जैविक पदार्थ जलाना, ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाला उत्सर्जन तथा कृषि अवशेषों का दहन इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं। सर्दियों में तापमान गिरने, हवा की गति कम होने और वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण प्रदूषक जमीन के निकट जमा हो सकते हैं। इससे प्रदूषण का प्रभाव अधिक गंभीर हो जाता है। इस प्रकार मौसम समस्या को बढ़ाता अवश्य है, लेकिन प्रदूषण पैदा करने वाले मूल कारण मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उनके अपर्याप्त नियमन से जुड़े हैं।

दिल्ली-एनसीआर की स्थिति इस संकट का सबसे स्पष्ट उदाहरण है। दिल्ली के साथ गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के अनेक शहर एक-दूसरे से जुड़े वायु क्षेत्र का हिस्सा हैं। इसलिए केवल दिल्ली की सीमाओं के भीतर उपाय करने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हवा किसी प्रशासनिक सीमा को नहीं मानती, वह प्रदूषण को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचाती है। अतः समाधान भी क्षेत्रीय सहयोग, साझा जवाबदेही और समन्वित कार्ययोजना पर आधारित होना चाहिए। वायु प्रदूषण का सबसे भयावह पक्ष उसका स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। विशेष रूप से पीएम 2.5 जैसे अत्यंत सूक्ष्म कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं और कुछ परिस्थितियों में रक्तप्रवाह तक प्रवेश कर सकते हैं। इनके लंबे समय तक संपर्क में रहने से हृदय एवं फेफड़ों संबंधी बीमारियों, स्ट्रोक और समयपूर्व मृत्यु का जोखिम बढ़ता है। बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा पहले से बीमार लोगों पर इसका प्रभाव विशेष रूप से गंभीर हो सकता है।

यह संकट केवल सांस के मरीजों तक सीमित नहीं है। स्वस्थ दिखाई देने वाले लोगों की कार्यक्षमता, एकाग्रता और जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को खुले मैदान में खेलने से रोकना पड़े, बुजुर्ग सुबह की सैर छोड़ने को विवश हों और श्रमिकों को जहरीली हवा में काम करना पड़े, तो यह केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि जीवन की गरिमा और नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़ा प्रश्न है। एयर प्यूरीफायर या मास्क कुछ परिस्थितियों में व्यक्तिगत बचाव में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे स्वच्छ हवा की सार्वजनिक व्यवस्था का विकल्प नहीं बन सकते। प्रदूषण बढ़ने पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत प्रदूषण की गंभीरता के अनुसार निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध, वाहनों और उद्योगों पर नियंत्रण तथा अन्य आपातकालीन कदम उठाए जाते हैं। लेकिन इन उपायों की सफलता केवल आदेश जारी करने से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और निरंतर निगरानी से सुनिश्चित होती है। यदि प्रतिबंधों का उल्लंघन होता रहे, निर्माण स्थलों पर धूल उड़ती रहे और कचरा खुले में जलता रहे, तो सरकारी घोषणाएं अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकतीं।

सरकार को प्रदूषण के चरम पर पहुंचने की प्रतीक्षा करने के बजाय सितंबर-अक्टूबर से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण, सड़कों की नियमित सफाई, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण और वाहनों के उत्सर्जन की जांच पहले से सुनिश्चित की जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना, इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देना, स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करना और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई करना दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। कृषि क्षेत्र में पराली जलाने की समस्या का समाधान किसानों पर जुर्माना लगाने भर से नहीं होगा। उन्हें फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए सस्ती मशीनें, तकनीकी सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन और स्थानीय स्तर पर उपयोग की सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। किसानों को समस्या का भागीदार नहीं, समाधान का सहयोगी बनाना होगा।

प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है। नागरिकों को निजी वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन अपनाने, कचरा और पत्तियां न जलाने तथा ऊर्जा की बचत करने जैसे कदम उठाने होंगे। पर्यावरण संबंधी नियमों के उल्लंघन की सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना और स्थानीय स्तर पर स्वच्छता एवं हरित क्षेत्र बढ़ाने के प्रयासों में भाग लेना भी आवश्यक है। मीडिया, शैक्षणिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों को जनजागरूकता अभियान चलाने चाहिए, ताकि स्वच्छ हवा का महत्व केवल प्रदूषण के चरम पर ही याद न आए। साथ ही, वायु गुणवत्ता के आंकड़े पारदर्शी ढंग से सार्वजनिक किए जाएं और नागरिकों को प्रदूषण के स्तर के अनुरूप स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी जाए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारें, उद्योग, किसान और नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटें। चीन के बीजिंग जैसे शहरों में प्रदूषण घटाने के अनुभव यह बताते हैं कि निरंतर नीतिगत प्रयास, स्वच्छ परिवहन, औद्योगिक नियंत्रण और प्रभावी निगरानी से उल्लेखनीय सुधार संभव है। भारत को भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे उपायों को दृढ़ता से लागू करना होगा। हर साल सर्दियों में प्रदूषण से जूझना और फिर मौसम बदलने पर समस्या को भूल जाना किसी भी संवेदनशील समाज की नियति नहीं हो सकती। स्वच्छ हवा कोई विलासिता नहीं, जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। यदि आज ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए प्रदूषण का मुकाबला संकट गहराने के बाद नहीं, उससे पहले करना होगा। सरकार की सक्रियता, प्रशासन की जवाबदेही और जनता की जागरूकता ही वह त्रिकोण है, जिसके आधार पर हम दमघोंटू हवा से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

अजेय कुमार बोले- महर्षि वाल्मीकि की ज्ञान-तपस्या प्रेरणादायी:समाज की वास्तविक शक्ति एकता-संस्कार; महर्षि वाल्मीकि की जयंती से पहले जयपुर में हुई महाआरती

आवाज ए तसनीम

जयपुर। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती से पहले रविवार को जयपुर में आस्था, श्रद्धा का संगम देखने को मिला। राजापार्क स्थित आदर्श विद्या मंदिर परिसर गोविंद मार्ग में आयोजित महाआरती में श्रद्धालुओं ने महर्षि वाल्मीकि भगवान के श्रीचरणों में श्रद्धा-सुमन अर्पित किए।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार मौजूद रहे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए उनके जीवन दर्शन, ज्ञान, तपस्या और सामाजिक समरसता के संदेश को संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायी बताया।

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने कहा- महर्षि वाल्मीकि भगवान भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और सामाजिक चेतना के महान पथप्रदर्शक हैं। उनका संपूर्ण जीवन ज्ञान, तपस्या, साधना, त्याग और मानव कल्याण का अनुपम उदाहरण है। उनके द्वारा रचित पवित्र रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता को सत्य, धर्म, मर्यादा, कर्तव्य और सदाचार का मार्ग दिखाने वाली अमूल्य धरोहर है।

उन्होंने कहा- समाज की वास्तविक शक्ति उसकी एकता, संस्कार और परस्पर सद्भाव में निहित है। जब समाज जाति, वर्ग और भेदभाव से ऊपर उठकर एक परिवार की भावना के साथ आगे बढ़ता है, तभी एक सशक्त, संगठित और समरस राष्ट्र का निर्माण होता है।

महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक

महर्षि वाल्मीकि भगवान का जीवन यह संदेश देता है कि व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म, चरित्र, ज्ञान और संस्कारों से निर्धारित होती है। उनके आदर्श समाज में समानता, भाईचारे और मानवता की भावना को सशक्त बनाते हैं।

उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी प्राचीन काल में थीं। उनके विचारों को केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण, व्यवहार और सामाजिक जीवन में आत्मसात करना चाहिए। विशेष रूप से युवा पीढ़ी को महर्षि वाल्मीकि जैसे महान ऋषियों के जीवन दर्शन से जोड़कर भारतीय संस्कृति, संस्कार और राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत बनाना आवश्यक है।

महाआरती में दिखा श्रद्धा, आस्था और सामाजिक समरसता का संगम

महाआरती के दौरान श्रद्धालुओं में श्रद्धा का वातावरण रहा। इस अवसर में विधायक प्रत्याशी रवि नैय्यर, भाजपा जयपुर शहर जिलाध्यक्ष अमित गोयल, जिला महामंत्री नवरत्न नारायणिया, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष गोविंद बाल्मीकि, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष विकास मीणा आदि मौजूद रहे।

संघ के शताब्दी वर्ष पर जयपुर में उद्भव-2026:2700 स्वयं सेवकों ने किया पथ संचलन, क्षेत्र कार्यवाह जसवंत खत्री ने कहा-संघ का उद्देश्य समाज को संगठित करना

आवाज ए तसनीम

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को जयपुर महानगर के मानसरोवर भाग में 'उद्भव 2026' विराट पथ संचलन एवं उत्सव आयोजित हुआ। अनुशासित कदमताल के साथ निकले स्वयंसेवकों ने संगठन शक्ति, राष्ट्रभक्ति और सामाजिक एकात्मता का संदेश दिया।

पथ संचलन में करीब 2700 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जबकि कार्यक्रम में लगभग 5 हजार गणवेशधारी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। वहीं आयोजन में बड़ी संख्या में आमजन की सहभागिता भी रही। इस मौके पर क्षेत्र कार्यवाह जसवंत खत्री ने संघ की 101 सालों की यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह यात्रा स्वयंसेवकों के त्याग, तपस्या, समर्पण और निरंतर परिश्रम का परिणाम है।

संघ का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज को संगठित करना और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए भारत को परम वैभव की ओर ले जाना है।

तीन संगम स्थलों से निकला पथ संचलन मानसरोवर क्षेत्र में पथ संचलन के लिए तीन प्रमुख संगम स्थल निर्धारित किए गए थे। तय रास्तों से होते हुए संचलन वीटी रोड चौराहा और न्यू सांगानेर रोड के संगम बिंदु पर एकत्रित हुआ।

पथ संचलन में बाल स्वयंसेवकों की सहभागिता भी आकर्षण का केंद्र रही। पहली बार संचलन में शामिल हुए बाल स्वयंसेवकों में विशेष उत्साह दिखाई दिया। सामूहिक कदमताल के अनुभव ने उनमें अनुशासन, एकजुटता और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव मजबूत किया।

करीब 2700 स्वंय सेवकों ने पथ संचलन में हिस्सा लिया।

करीब 2700 स्वंय सेवकों ने पथ संचलन में हिस्सा लिया।

पंच परिवर्तन से बदलेगा सामाजिक जीवन

कार्यक्रम में पंच परिवर्तन के पांच प्रमुख आयामों-सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्व का बोध, कुटुंब प्रबोधन और नागरिक शिष्टाचार को समाज जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बताया गया।

वहीं मुख्या वक्ता ने कहा कि सज्जन शक्ति को संगठित कर युवाओं, परिवारों और समाज के विभिन्न वर्गों को राष्ट्रहित के कार्यों से जोड़ना होगा, साथ ही सामाजिक परिवर्तन के लिए विचारों के साथ व्यवहार में भी बदलाव लाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सरपंच चुनाव हारी प्रत्याशी को ग्रामीणों ने दिए 25 लाख:आपसी सहमति से इलेक्शन लड़वाया था, बोले-भाईचारा और एकता हार-जीत से बड़ी है

आवाज ए तसनीम

नागौर। गले में माला, सिर पर साफा और हाथों में रुपयों से भरा थाल। तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारे। ये नजारा नागौर की मूंडवा पंचायत समिति की भदौरा ग्राम पंचायत के सरपंच चुनाव में हारीं चिड़ी देवी के घर का है।

गांव के लोगों ने सहमति से चिड़ी देवी को चुनाव लड़ाया था। हारने के बाद गाड़ियों में भरकर चिड़ी देवी के घर पहुंचे। सहयोग से जुटाए 25 लाख रुपए थाल में रखकर उनके पति हेमाराम को दिए। ग्रामीणों ने कहा-चुनाव में जीत-हार अपनी जगह है, आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता इससे कहीं बड़ी है।

ग्रामीणों ने आपसी सहमति से चुना था प्रत्याशी

भदौरा ग्राम पंचायत के गांव मोड़ी में रहने वाली चिड़ी देवी (45) किसान परिवार से हैं। उनके पति हेमाराम राव खेती करते हैं। करीब 2 साल पहले उन्होंने गांव की गोशाला में एक ट्रैक्टर भेंट किया था और एक प्याऊ भी बनवाई थी। बोरवेल खुदवाने की घोषणा की थी। उनकी समाज सेवा से प्रभावित ग्रामीणों ने इस बार भदौरा ग्राम पंचायत महिला सीट होने पर मोड़ी गांव के लोगों ने आपसी सहमति से हेमाराम राव की पत्नी चिड़ी देवी को सरपंच पद का प्रत्याशी बनाया था।

वहीं, चिड़ी देवी के सामने भदौरा गांव से रिटायर्ड थानेदार माधोसिंह की पुत्रवधू गिरिजा सान्दू चुनाव मैदान में थीं। गिरिजा सान्दू ने चिड़ी देवी को 162 वोटों से हरा दिया। गिरीजा को 1317 वोट मिले, जबकि चिड़ी देवी को 1155 वोट मिले थे।

हार के बाद ग्रामीणों ने जुटाए 25 लाख रुपए

चुनाव परिणाम आने के बाद ग्रामीणों ने गांव में सभा की। आपसी सहयोग से 25 लाख रुपए इकट्ठा किए। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण गाड़ियों में भरकर हेमाराव के घर पहुंचे और 25 लाख रुपए थाल में सजाकर हेमाराम राव को भेंट किए।

बोले- सरपंच नहीं बनने का मलाल था

हेमाराम राव ने कहा - सरपंच नहीं बन पाने का मलाल मन में था, लेकिन गांव के लोगों ने इस पल को गर्व और खुशी में बदल दिया। पद मिले या नहीं, पूरे गांव का साथ और अपनापन ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। गांव के लोगों ने सहमति से प्रत्याशी चुना था। ग्रामीणों ने कहा था जीतेगा तो गांव जीतेगा और हारेगा तो गांव हारेगा।

उदयपुर में सीआई को हटाने की मांग पर अड़े वकील:3 घंटे थाने में विरोध-प्रदर्शन; एएसपी-डीएसपी ने की समझाइश

आवाज ए तसनीम

उदयपुर। उदयपुर में एक वकील को जान से मारने की धमकी देने के मामले में कानूनी कार्रवाई नहीं करने से नाराज वकील थाने में धरने पर बैठ गए। आक्रोशित वकील रविवार दोपहर को सवीना थाने के सीआई दलबीर सिंह के खिलाफ नाराजगी जताते हुए उन्हें हटाने की मांग पर अड़ गए।

वकीलों का आरोप था कि साथी वकील राजेश जाजोदिया रविवार दोपहर को शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो आरोपी कौशल आमेटा भी थाने पहुंचा। वहीं पुलिस के सामने ही वकील को जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। माहौल गर्माया तो एडिशनल एसपी उमेश ओझा, डीएसपी छवि शर्मा जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और वकीलों से समझाइश का प्रयास किया। करीब 3 घंटे बाद रात करीब 9 बजे मामला शांत हुआ।

सीआई की लापरवाही से पनप रहे भूमाफिया: चेतनपुरी गोस्वामी

वकीलों ने एएसपी उमेश ओझा को सीआई दलबीर के खिलाफ लिखित शिकायत देते हुए उन्हें हटाने की मांग की। मामले में एएसपी ओझा ने बताया कि वे इसे एसपी डॉ अमृता दुहन के समक्ष रखेंगे और एसपी स्तर से ही मामले में संज्ञान लिया जाएगा।

पूर्व महासचिव चेतनपुरी गोस्वामी ने बताया- मामला साथी वकील राजेश जाजोदिया के रिश्तेदार गोविंद नगर में देवेन्द्र अग्रवाल के प्लॉट से जुड़ा है। आरोपी कौशल आमेटा प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। प्लॉट मालिक प्लॉट की रविवार को सफाई कर रहे थे। तब आरोपी आमेटा ने वकील और प्लॉट मालिक पर पथराव किया। वकील ने इसकी रिपोर्ट थाने में दी तो कोई सुनवाई नहीं हुई।

अजमेर-डिस्कॉम के 14जिलों में किसानों को मिलेगी दिन में बिजली:सरकार का दावा- 26 जिलों में किसानों को दिन में दे रहे बिजली; 2027 तक सभी जिलों में देंगे

आवाज ए तसनीम

जयपुर। अजमेर डिस्कॉम के 14 जिलों के किसानों को अब दिन में बिजली मिलेगी। दरअसल, नागौर जिले के बिरलोका में 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन (जीएसएस) शुरू हो गया है। इसके बाद अब अजमेर विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) के सभी 14 जिलों में किसानों को दिन के समय दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति मिल सकेगी।

अभी तक अजमेर डिस्कॉम के 14 में से 13 जिलों में किसानों को दिन में दो ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था लागू थी। बिरलोका जीएसएस के शुरू होने से शेष जिले में भी इस व्यवस्था का विस्तार होगा।

इस परियोजना से बिरलोका, नारवा, हिसाबा, पांचला सिद्धा, खींवसर, पांचौड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से संपूर्ण खींवसर तहसील में किसानों को दिन के समय दो ब्लॉक में बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

सरकार ने कहा- इस व्यवस्था से क्षेत्र के किसानों को रात में सिंचाई कार्य से राहत मिलेगी तथा खेती कार्य अधिक सुरक्षित एवं सुविधाजनक हो सकेगा।

170 करोड़ की लागत से बना जीएसएस

लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस जीएसएस में 160 एमवीए क्षमता का 220/132 केवी पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित किया गया है। अत्याधुनिक स्काडा प्रणाली के उपयोग से पश्चिमी राजस्थान में उत्पादित सौर ऊर्जा का नागौर जिले में बेहतर उपयोग संभव होगा।

इसके साथ ही विद्युत छीजत में कमी आएगी और वोल्टेज स्तर, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा।

सरकार का दावा- 26 जिलों में दिन में बिजली दे रहे

दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साल 2027 तक प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की बजट घोषणा की थी। सरकार का दावा है कि इस दिशा में प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए अब तक प्रदेश के 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

नरेश मीणा के खिलाफ अधिकारियों को धमकाने का मामला दर्ज:बोले- मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के दबाव में FIR हुई, मुझे फिर जेल भेजना चाहते हैं

आवाज ए तसनीम

जयपुर। किसान नेता नरेश मीणा के खिलाफ बारां जिले के छबड़ा थाने में अधिकारियों को धमकाने समेत 8 धाराओं में स्नढ्ढक्र दर्ज की गई है। मामले को लेकर कृषि उपनिदेशक ने कलेक्टर को शिकायत भेजी थी। नरेश मीणा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के दबाव में कृषि विभाग के अधिकारियों ने यह केस दर्ज कराया है। उन्होंने कहा- पंचायत चुनाव के बीच सरकार हमें जेल भेजना चाहती है, लेकिन जेल जाने के बाद भी जनता मेरा साथ देगी और 'हाथी' चुनाव चिह्न पर वोट देकर पंचायतराज चुनाव में मेरा बोर्ड बनाएगी।

अब तक सरकार 40 से अधिक मुकदमे दर्ज करा चुकी

नरेश मीणा ने कहा- यह मुकदमा पहली बार दर्ज नहीं हुआ है। अब तक सरकार मेरे ऊपर 40 से अधिक मुकदमे दर्ज करा चुकी है। कई बार जेल भी भेजा जा चुका हूं। जब भी मैं जनता की आवाज उठाता हूं, जनता के लिए लड़ता हूं, तब मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। दबाव बनाया जाता है कि मैं जनता की आवाज न बनूं। उन्होंने कहा- पिछले दिनों मुझे बिना कारण 45 दिन जेल में रखा गया, केवल इसलिए कि मैंने पिपलौदी में मरने वाले बच्चों की मदद की और उनके लिए आंदोलन किया।

अधिकारियों ने कृषि मंत्री के दबाव में दर्ज कराया मामला

नरेश मीणा ने कहा- किसानों को खाद दिलाने के लिए आंदोलन किया, तब भी यही हुआ। बड़े लोगों को खाद मिल रहा था, गरीबों को नहीं मिल रहा था। गर्भवती महिलाएं और छोटे-छोटे बच्चे 14-14 घंटे खाद की लाइन में लग रहे थे। यह मैं सहन नहीं कर पाया। इस पर मैंने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और अधिकारियों को उनके दायित्व निर्वहन के लिए चेतावनी दी।

नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि यह मुकदमा पुलिस द्वारा नहीं, बल्कि कृषि विभाग द्वारा दर्ज कराया गया है। इससे यह तय है कि यह मुकदमा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के दबाव में दर्ज कराया गया है, जिसमें कई ऐसी धाराएं हैं जिनमें 7 साल तक की सजा है।

तुम मुझे जेल में डाल सकते हो, मेरी सोच को नहीं

उन्होंने कहा- जब-जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा-चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से...मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम नरेश मीणा को सलाखों के पीछे डाल सकते हो, लेकिन अब नरेश मीणा एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है, एक विचार है। आज हाड़ोती के घर-घर में नरेश मीणा खड़े हो गए हैं। तुम मुझे जितनी बार जेल में डालोगे, उतना ही हर किसान का बेटा नरेश मीणा बनकर ढाल बनेगा और तुम्हारे नकाब को बेनकाब करेगा।

उन्होंने भरोसा जताया कि अगर उन्हें जेल भेजा भी गया, तो भी हर घर से नरेश मीणा सड़क पर निकलेगा और इस चुनावी दंगल को आंदोलन बनाएगा। हाथी को बहुमत के रूप में जिला प्रमुख और प्रधानों के रूप में 12 जिलों का बोर्ड बनेगा।

दरअसल, छबड़ा में 22 अक्टूबर को खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने हाईवे जाम कर दिया था। सूचना पर नरेश मीणा मौके पर पहुंचे और किसानों के साथ खेल मैदान में आए और पेड़ पर चढ़कर सभी को संबोधित किया था। हजारों किसानों के साथ हाथ में लाठी लेकर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। छबड़ा एसडीएम सपना कुमारी ने मौके पर पहुंचकर नरेश मीणा और किसानों से बातचीत की थी। इसके बाद प्रशासन ने पुलिस की निगरानी में डीएपी के टोकन वितरण की व्यवस्था शुरू करवाई थी।

जयपुर में धूमधाम से मना जश्न-ए-सर सैयद 2026 : AMUOBA राजस्थान ने सर सैयद के शैक्षिक मिशन को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प

जयपुर में धूमधाम से मना जश्न-ए-सर सैयद 2026 : AMUOBA राजस्थान ने सर सैयद के शैक्षिक मिशन को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प

कलेक्टर कमर उल ज़मान चौधरी बोले–'अवसर का लाभ उठाएं, शिकायतें कमजोर लोग करते हैं'

आवाज ए तसनीम

जयपुर। महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (रू) के संस्थापक सर सैयद अहमद ख़ाँ की जयंती के उपलक्ष्य में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन (रूह्वक्क) राजस्थान चैप्टर की ओर से रविवार को शहर के होटल इंडियाना प्राइड में 'जश्न-ए-सर सैयद 2026' का गरिमामय आयोजन किया गया। इस भव्य जलसे में शिक्षा के प्रसार, सामाजिक सुधार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पारस्परिक सौहार्द और सामुदायिक विकास को गति देने के साथ ही सर सैयद अहमद ख़ाँ के प्रगतिशील शैक्षिक मिशन को जन-जन तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि भरतपुर के जिला कलेक्टर कमर उल ज़मान चौधरी रहे, जबकि अध्यक्षता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और रूह्वक्कराजस्थान चैप्टर के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आज़म बैग ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ आयकर आयुक्त फरहा ख़ान (ढ्ढक्रस्), जाने-माने वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. सैफुल हक़, सेवानिवृत्त ढ्ढक्रस् अधिकारी यू.डी. ख़ान, डॉ. शौकत अली और वरिष्ठ अलीग एफ.के. शेरवानी मंचस्थ रहे।

'शिकायतें कमजोर लोग करते हैं, मौकों को भुनाएं युवा': कलेक्टर कमर उल ज़मान चौधरीमुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए भरतपुर कलेक्टर कमर उल ज़मान चौधरी ने कहा कि सर सैयद अहमद ख़ाँ की विचार दृष्टि और विरासत आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 19वीं सदी में थी। समाज के समग्र उत्थान के लिए आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन ही सबसे प्रभावी माध्यम हैं। युवाओं में ऊर्जा का संचार करते हुए उन्होंने कहा:

'जीवन में उपलब्ध अवसरों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें, क्योंकि बार-बार शिकायतें करना कमजोर लोगों की पहचान है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, संसाधनों का सदुपयोग करें और अपने निर्धारित लक्ष्यों के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहें। '

1857 के बाद सर सैयद ने शिक्षा को बनाया रोशनी का माध्यम: डॉ. आज़म बैगसमारोह की अध्यक्षता करते हुए डॉ. आज़म बैग ने सर सैयद के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति के बाद जब समाज गहरे अवसाद और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था, तब सर सैयद अहमद ख़ाँ ने आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और तालीम को तरक्की का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने आधुनिक व नैतिक शिक्षा के द्वार खोलकर कौम और मुल्क को एक नई दिशा दी।

डॉ. बैग ने आह्वान किया कि आज भी उनके इस कारवां को उसी शिद्दत से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि नई पीढ़ी के सामने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अवसर तैयार किए जा सकें।

अकादमिक, चिकित्सा, सामाजिक और पत्रकारिता जगत की प्रतिभाओं का सम्मानसमारोह के दौरान मुख्य अतिथि कमर उल ज़मान चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आज़म बैग, वरिष्ठ आयकर आयुक्त फरहा ख़ान और डॉ. शौकत अली ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों को स्मृति चिह्न व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

अकादमिक एवं चिकित्सा क्षेत्र:

डॉ. साइब हुसैन, डॉ. सना बेग, प्रो. नौशी मुजीब, प्रो. फौज़िया सआदत, प्रो. मोहम्मद आज़म अंसारी, प्रो. महमूद सलीम, प्रो. सिराजुल हक़, प्रो. मोहम्मद शोएब आज़मी, डॉ. सदफ़ नवाज़, डॉ. सफिया हुसैन, डॉ. फैयाज़ ख़ान और हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान को उनके विशिष्ट योगदान के लिए नवाजा गया।

मीडिया एवं पत्रकारिता:

निष्पक्ष पत्रकारिता और जनसरोकारों को प्रमुखता से उठाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एम.आई. ज़ाहिर, बाबू अंसारी, नईम अहमद, इस्माइल ख़ान और अबरार त्यागी को सम्मानित किया गया।

इसके अलावा समाज सेवा, स्वास्थ्य सेवा और जनकल्याणकारी कार्यों में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान की भी मुक्तकंठ से सराहना की गई।

एएमयू तराने के हिंदी अनुवाद के साथ हुआ समापन

कार्यक्रम का आगाज़ प्रो. शौकत अली के स्वागत भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने सामाजिक सद्भाव और शिक्षा के प्रसार में साझा प्रयासों की जरूरत बताई। पूरे कार्यक्रम का कुशल मंच संचालन डॉ. सना बेग ने किया।

समारोह का समापन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक और विश्वप्रसिद्ध तराने के हिंदी अनुवाद के सामूहिक गायन के साथ हुआ। 'जश्न-ए-सर सैयद 2026' ने न केवल एएमयू की गौरवशाली परंपरा और तहज़ीब की याद ताजा की, बल्कि आपसी भाईचारे और गंगा-जमुनी तहज़ीब को मजबूत करने का एक सशक्त संदेश भी दिया।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी बोलीं- गांवों का विकास हमारी प्राथमिकता:परबतसर में भाजपा पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं से की बात, विकास के लिए काम करने के लिए किया प्रेरित

आवाज ए तसनीम

परबतसर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को परबतसर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम बडू और पीलवा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने गांवों के विकास और ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने पर जोर दिया।

डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हमारी प्राथमिकता है। जनसभा के बाद उन्होंने ग्रामीणों, भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया।

ग्राम बडू में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी डिप्टी सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सशक्त ग्राम पंचायतें ही सशक्त राजस्थान की आधारशिला हैं।

गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर और सुविधासंपन्न बनाना जरूरी है।

इसके बाद उपमुख्यमंत्री ने पंचायत समिति पीलवा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों से भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति बनाए रखना और प्रत्येक गांव तक विकास के अवसर पहुंचाना जरूरी है।

दिया कुमारी ने ग्राम पंचायतों को सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के संकल्प को दोहराते हुए 'विकसित ग्राम पंचायत से विकसित राजस्थान' के लक्ष्य को साकार करने का आह्वान किया।

भाजपा पदाधिकारी और प्रत्याशी रहे मौजूद

कार्यक्रम में पूर्व विधायक मान सिंह किनसरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष सुनीता रांदड़, चुनाव जिला प्रभारी रणजीत सिंह सोडाला, चुनाव प्रभारी मानवेंद्र सिंह कुड़की, जिला महामंत्री देवीलाल, मंडल अध्यक्ष दयाल मेघवाल, ठाकुर महेश पाल सिंह और प्रभारी संपत सांखला सहित कई नेता मौजूद रहे।

इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रत्याशी, भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

حوثیوں کا مکہ اور مدینہ پر حملوں سے انکار
لیکن سعودی عرب کا دعویٰ کچھ اور بتاتا ہے!

ایران کے حمایت یافتہ یمنی حوثی گروپ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ اس نے اسلام کے دو مقدس ترین شہروں مکہ اور مدینہ کو نشانہ بنایا ہے لیکن سعودی عرب نے کہا کہ اس نے ان علاقوں کی طرف داغے گئے میزائلوں کو روکا اور کئی مقامات پر ملبہ گرنے کی اطلاع ملی۔ حوثیوں نے کہا کہ ان کی فوجی کارروائیوں میں سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ گروپ نے کہا کہ وہ ایسے کسی بھی حملے کا عوامی طور پر اعلان کرتا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے یہ تردید ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان سرحد پار سے کشیدگی ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب کی سول ڈیفنس ایجنسی نے بتایا کہ دو بیلسٹک میزائلوں کے ٹکڑے مکہ اور مدینہ کے علاقوں میں گرے۔ مکہ کے قریب اور جدہ، طائف اور ربیعہ میں بھی ملبے کی اطلاع ملی ہے۔ تاہم حوثیوں نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کو نشانہ نہیں بنایا۔ سعودی عرب نے حوثیوں کے اس دعوے پر فوری طور پر کوئی ردعمل نہیں دیا۔

سعودی زیر قیادت اتحاد نے کہا کہ اس نے ینبو اور طائف کی طرف داغے گئے دو بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا۔ تاہم، سعودی حکام نے دوسرے اہداف پر حملوں کے حوثیوں کے دعووں کا براہ راست جواب نہیں دیا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ آیا ان حملوں میں سے کوئی بھی میزائل اپنے اہداف تک پہنچا یا درمیانی فضا میں ہی روکا گیا۔ سعودی حکام نے رابغ سمیت کئی مقامات پر میزائل کا ملبہ ملنے کی اطلاع دی۔ حوثیوں نے ربیغ آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ تازہ ترین تنازعہ نے اقوام متحدہ کی ثالثی میں 2022 میں دستخط کی گئی جنگ بندی کو نقصان پہنچایا ہے۔ اس جنگ بندی کے بعد سعودی قیادت والے اتحاد اور حوثیوں کے درمیان سرحد پار سے حملے بڑی حد تک بند ہو گئے تھے۔ سعودی زیر قیادت اتحاد یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کرتا ہے جبکہ حوثیوں کا دارالحکومت صنعا اور ملک کے شمالی حصہ کے بڑے حصوں پر کنٹرول ہے۔ حالیہ کشیدگی نے ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی وسیع جنگ میں ایک اور محاذ کھول دیا ہے۔ ایران کے ساتھ اتحادی حوثی فورسز نے سعودی اڈوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔

کیا راہول سکھ برادری کے زخموں پر نمک چھڑکنا چاہتے ہیں؟
رام لیلا میدان میں یکم نومبر کو کانگریس کی ریالی پر روی شنکر پرساد کا استفسار

آوازِ تسنیم: بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے کانگریس کی جانب سے یکم نومبر کو یہاں کے رام لیلا میدان میں مجوزہ ریلی پر تنقید کرتے ہوئے اسے سکھ برادری کے زخموں پر نمک چھڑکنے والا قدم قرار دیا۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے ہفتہ کو پارٹی ہیڈکوارٹر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یکم نومبر سکھ برادری کے جذبات سے وابستہ دن ہے، کیونکہ 1984 میں اسی دن قتل عام ہوا تھا۔ سکھ برادری اس دن کو انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کانگریس لیڈر راہول گاندھی یکم نومبر کو ہی دہلی میں ریلی کرنے پر کیوں بضد ہیں؟ کیا وہ یکم نومبر کو رام لیلا میدان میں ریلی کر کے سکھ برادری کے زخموں پر نمک چھڑکنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ گاندھی کا اصل چہرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ”میں ضدی ہوں، بہت ضدی ہوں اور کسی کی بات نہیں سنتا! میری ضد یہ ہے کہ میں ظالمانہ طریقے سے سکھ برادری کے جذبات کا مذاق اڑاؤں گا۔“ بی جے پی لیڈر نے کہا کہ جب ان کے والد راجیو گاندھی ہندوستان کے وزیر اعظم تھے، تو اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے بدقسمتی سے قتل اور اس کے بعد ہونے والے فسادات کے تناظر میں انہوں نے ایک انتہائی مشہور بیان دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی بڑا درخت گرتا ہے تو زمین ہلتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان لوگوں نے 1984 کے فسادات کی سنگینی کو کم کر کے دکھانے اور ان کے ذمہ دار لوگوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے کہا ”آج مجھے فخر ہے کہ جب مودی حکومت اقتدار میں آئی تو خصوصی تحقیقاتی ٹیم (ایس آئی ٹی) کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ جن سکھوں کا قتل ہوا تھا، ان کے اہل خانہ کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا معاوضہ دیا گیا اور دہلی میں ہزاروں لوگوں کو بھی یہ معاوضہ ملا۔ بعد میں کئی قصورواروں کو سزا بھی ہوئی اور بعض کو سزائے موت تک دی گئی۔“ پرساد نے سوال کیا کہ گاندھی یکم نومبر کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ہنگامہ آرائی، افراتفری یا توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ”میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ راہول گاندھی کی قیادت میں دہلی میں اب تک ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شائستگی کی تمام حدیں پار کی گئی ہیں۔“ انہوں نے بتایا کہ دہلی کے تجارتی و صنعتی چیمبر نے راہول گاندھی کو خط لکھ کر درخواست کی ہے کہ براہ کرم یکم نومبر کی ریلی ملتوی کر دی جائے اور تاجروں کے مفاد میں اس ریلی کو 10 نومبر کے بعد منعقد کرنے پر غور کیا جائے۔ انہوں نے کہا ”گاندھی، آپ کو بی جے پی اور وزیر اعظم نریندر مودی جی سے چڑ ہے، لیکن کیا آپ کو ملک کے عام لوگوں اور تاجروں سے بھی چڑ ہے؟ آپ ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، یہ آپ کی ضد ہے۔“ انہوں نے کہا ”قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے میں پہلی بار پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے سپریم کورٹ یا کسی دوسری عدالت کا گھیراؤ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ کسی سیاسی جماعت، لیڈر یا تنظیم نے کسی عدالت کے باہر گھیراؤ یا مخالفانہ مظاہرہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔“ اس دوران بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ نے یہاں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں متنازع نعروں کے لکھے جانے کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش کانگریس کے کارگزار صدر اور رکن پارلیمنٹ عمران مسعود کیا کر رہے تھے؟ وہاں دیواروں پر 'کشمیر کو آزاد کرو' اور 'شرجیل امام کو رہا کرو' جیسے نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں جا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کانگریس سے پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا کانگریس جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بڑے بڑے حروف میں لکھے ہندوستان سے کشمیر کو الگ کرنے کے مطالبے کی حمایت کرتی ہے؟ ہندوستان کو توڑنے کی بات کرنے والے شرجیل امام کے بارے میں کانگریس پارٹی کا کیا موقف ہے؟ وہاں پوری چار دیواری پر بڑے بڑے حروف میں 'کشمیر کو آزاد کرو' اور 'شرجیل امام کو رہا کرو' کے نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی شرجیل امام ہے، جس کی ضمانت کی عرضی بار بار مسترد ہو چکی ہے۔ یہ وہی شخص ہے، جس نے چکن نیک راہداری کو کاٹ کر مشرقی ہندوستان کا رابطہ پوری طرح منقطع کرنے اور اسے بنگلہ دیش کے حوالے کرنے کی بات کہی تھی۔

ٹائیگر شراف فائرنگ معاملہ: پولیس نے اندور سے کی 11 ویں کی گرفتاری

آوازِ تسنیم: بالی ووڈ اداکار ٹائیگر شراف سے جڑے فائرنگ معاملے میں پولیس نے 11 ویں گرفتاری کر لی ہے۔ ممبئی کرائم برانچ نے ہریانہ کے سونی پت ضلع کے ہرسانہ گاؤں کے رہنے والے پرانجل کو اندور سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق شوٹروں تک ہتھیار اور زندہ کارتوس پہنچانے میں اس کا اہم کردار تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ملزم کی نشاندہی پر گجرات کے سورت سے 3 غیر قانونی ہتھیار اور 10 کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ ٹائیگر شراف فائرنگ معاملے میں اب تک گرفتار کیے گئے 11 ملزمین میں سے 8 سونی پت ضلع کے رہنے والے ہیں۔ پرانجل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد اہل خانہ نے پولیس کی کارروائی پر سوال اٹھائے ہیں۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے اور اسے غلط طریقے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانجل کا ٹائیگر شراف فائرنگ معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اہل خانہ کے مطابق پرانجل اندور میں اپنے بھائی کے پاس تھا، جو وہاں کے ایک اسپتال میں داخل ہے اور اس کا علاج جاری ہے۔ خاندان کا کہنا ہے کہ پرانجل اپنے بھائی کی دیکھ بھال کیلئے وہاں موجود تھا۔ اسی دوران ممبئی کرائم برانچ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اہل خانہ اپنے بیٹے کو بے قصور قرار دے رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس کا فائرنگ کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تحقیقات کے دوران پرانجل کا تعلق پہلے گرفتار کیے جا چکے ملزم کنال کے ساتھ بھی سامنے آیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پانی پت میں ہوئی فائرنگ کے واقعہ میں کنال کے ساتھ پرانجل کا نام بھی سامنے آیا تھا۔ دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی تھی۔ پولیس کی تحقیقات میں یہ کڑی بھی سامنے آئی ہے، جس کی بنیاد پر پرانجل کے کردار کی جانچ کی جا رہی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ٹائیگر شراف فائرنگ معاملے میں یہ 11 ویں گرفتاری ہے۔ پولیس کے مطابق پرانجل سے متعلق سراغوں کی بنیاد پر سورت سے 3 غیر قانونی ہتھیار اور 10 زندہ کارتوس برآمد کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب اہل خانہ مسلسل اس کی بے گناہی کا دعویٰ کر رہے ہیں۔

☆☆☆

’ملک بھر میں جین۔زی طبقہ سڑکوں پر اتر رہا ہے
کانگریس نے خراب حالات کیلئے مودی حکومت کو ٹھہرایا ذمہ دار

آوازِ تسنیم: ملک بھر میں نوجوان طبقہ مختلف مواقع پر ایس آئی آر اور بے روزگاری کے خلاف سڑکوں پر نکل کر احتجاجی مظاہرہ کر ہی رہا ہے، کچھ ریاستوں میں الگ الگ مطالبات کیلئے بھی مظاہرے جاری ہیں۔ اروناچل پردیش میں مجوزہ ’ایس یو ایم پی‘ منصوبہ کے خلاف جین-زی طبقہ احتجاج کرتا دکھائی دے رہا ہے، جس کے خلاف گزشتہ روز پولیس نے آنسو گیس کا گولہ داغ کر نوجوانوں کو مشتعل کر دیا۔ اس بارے میں کانگریس کے سینئر لیڈر پون کھیڑا نے سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک بھر میں جین-زی طبقہ سڑکوں پر اتر رہا ہے اور اس خراب صورت حال کے لیے مودی حکومت ذمہ دار ہے۔ پون کھیڑا نے اس بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ ”ملک بھر میں جین-زی سڑکوں پر ہے۔ دہلی میں اس کی وجہ تعلیم ہے جبکہ اروناچل پردیش میں قبائلی طبقہ کے لوگ ان جنگلات، ندیوں اور ماحولیاتی نظام کے تحفظ کو توجہ میں رکھتے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں جن پر وہ صدیوں سے انحصار کرتے ہیں۔“ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ”دہلی سے اروناچل پردیش تک مودی حکومت نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا ہے اور وہ ہے ’جبر‘ کا۔ دہلی میں طلبا کے احتجاجی مظاہرہ پر ہونے والی کارروائی کی یاد تازہ کرتے ہوئے اروناچل پردیش میں بھی پُرامن مظاہرین پر آنسو گیس کے گولے داغے گئے۔“ قابل ذکر ہے کہ آنسو گیس کے یہ گولے سیکورٹی عہدیداروں کے ذریعہ داغے گئے تھے جس نے جین-زی طبقہ کو مشتعل کر دیا۔ اس کے بعد پولیس پر پتھراؤ کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ پون کھیڑا نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں پولیس ایکشن کے وقت کی ایک ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں ایک خاتون رپورٹر پریشان حال ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایک رپورٹر کی حیثیت سے نہیں، بلکہ جین-زی اور شہری کی حیثیت سے وہ ویڈیو بنا رہی ہے اور آرمڈ فورسز نے پُرامن مظاہرین پر کارروائی کر مشکل حالات پیدا کر دیے ہیں۔ ویڈیو بنانے والی خاتون یہ بھی بتاتی ہے کہ آنسو گیس کی وجہ سے لوگوں کو دقتیں ہو رہی ہیں۔ انہیں آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں تکلیف کا بھی سامنا ہے۔ وہ سوال کرتی ہیں کہ اگر اس آنسو گیس کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آخر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بہرحال، اس پوسٹ میں پون کھیڑا نے اروناچل پردیش میں پیدا حالات کے پیچھے موجود وجہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ قبائلی لوگ ایک مذہبی اور ثقافتی اقلیت ہیں، جن کے عقائد اور روایات دریائے سیانگ اور اس سے متصل جنگلات سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ وہ ’اَپر سیانگ‘ خطہ میں مجوزہ 11 ہزار میگاواٹ کے باندھ (ڈیم) کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ان قدرتی وسائل کے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے اس معاملہ میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی بے حسی اور مرکزی وزیر کرن رجیجو کی خاموشی پر افسوس بھی ظاہر کیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ”چونکہ امت شاہ دہلی پولیس کو شکریہ ادا کرنے کیلئے فون کرنے میں مصروف ہیں، اس لیے کیا اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو برائے مہربانی یہ وضاحت کریں گے کہ وہ اپنی آبائی ریاست میں قبائلی لوگوں کے اقلیتی حقوق کے تحفظ کیلئے کیا کر رہے ہیں؟“۔

طائف اور ینبع پر 2 میزائل حملوں کو ناکارہ بنا دیا گیا
مکہ اور جدہ میں الرٹ جاری ہونے کے چند منٹ بعد واپس لے لیا گیا

آوازِ تسنیم: یمنی حوثیوں سے لڑنے والے سعودی اتحاد نے بتایا ہے کہ ہفتے کے روز طائف اور ینبع کی طرف داغے گئے دو حوثی بیلسٹک میزائلوں کو تباہ کر دیا گیا جبکہ فریقین کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ سعودی عرب کے سول ڈیفنس نے ہفتے کے روز طائف اور ینبع کے ساتھ ساتھ مقدس شہر مکہ اور ملک کے دوسرے بڑے شہر جدہ میں ممکنہ خطرے کے پیش نظر کچھ دیر کے لیے الرٹس جاری کیے۔ سعودی سول ڈیفنس ایجنسی نے ہفتے کے روز اپنی چار مغربی گورنریوں بشمول مکہ کے لیے "ممکنہ خطرے" کی وارننگ جاری کی۔ تاہم چند منٹ بعد ہی یہ تمام الرٹس واپس لے لیے گئے۔ ایجنسی نے "میزائلوں اور ڈرونز کو ناکارہ بنانے" سے متعلق تصاویر یا معلومات کا اشتراک کرنے کے خلاف قانونی کارروائی کے انتباہ کا بھی اعادہ کیا۔ سعودی عرب کے محکمہ شہری دفاع نے ملک کے مغربی حصے کے چار علاقوں میں ممکنہ خطرے سے متعلق ہنگامی انتباہ جاری کیا، جن میں مکہ مکرمہ، جدہ، طائف اور ساحلی شہر ینبع شامل ہیں۔ تاہم یہ انتباہ جاری ہونے کے چند منٹ بعد ہی واپس لے لیے گئے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق، سعودی شہری دفاع نے متعلقہ علاقوں کے رہائشیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ فوری طور پر قریبی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین شہر ہے، جبکہ جدہ بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ایک اہم شہر ہے۔ محکمہ شہری دفاع نے انتباہ واپس لینے کے بعد بھی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات دیں۔ حکام نے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے یا ان کے خلاف کارروائی سے متعلق تصاویر اور معلومات سوشل میڈیا یا دیگر ذرائع پر شیئر کرنے کے خلاف قانونی تنبیہ بھی دہرائی۔ رپورٹ میں فوری انتباہ جاری کیے جانے کی وجہ، کسی میزائل یا ڈرون کی موجودگی اور ممکنہ نقصان سے متعلق تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں۔ حکام کی جانب سے الرٹ واپس لیے جانے کے بعد ان علاقوں میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع بھی رپورٹ میں شامل نہیں ہے۔

انتخابی حلف نامہ میں معلومات چھپانے پر عام شہری بھی کر سکیں گے شکایت: سپریم کورٹ

آوازِ تسنیم: ووٹرس کو اب انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے ساتھ ہی امیدوار کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ کوئی بھی عام ووٹر یا شہری انتخابی امیدواروں کے خلاف براہ راست مجرمانہ شکایت درج کرا سکتا ہے۔ اگر کوئی امیدوار انتخابات کے وقت جمع کرائے گئے حلف نامے میں غلط معلومات دیتا ہے یا ضروری معلومات چھپاتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ کارروائی عوامی نمائندگی ایکٹ، 1951 کی دفعہ 125-A کے تحت کی جا سکتی ہے۔ اس شکایت کے لیے الیکشن کمیشن یا کسی سرکاری افسر کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے واضح کیا کہ اس معاملے میں کوڈ آف کریمنل پروسیجر (سی آر پی سی) کی دفعہ 195 کی شرائط لاگو نہیں ہوتیں، جس کے باعث عام شہری براہ راست شکایت درج کرا سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عوامی نمائندگی ایکٹ، 1951 کی دفعہ 125-A کے تحت جرم (جس میں امیدوار کی جانب سے جھوٹا حلف نامہ داخل کرنا بھی شامل ہے) کے خلاف دائر کی گئی ذاتی شکایت قانونی طور پر قابل قبول ہے۔ اس کے لیے سی آر پی سی کی دفعہ 195 (بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا میں دفعہ 215) کے تحت کسی سرکاری ملازم کی جانب سے شکایت درج کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 125-a ان امیدواروں کے لیے سزا کا التزام کرتی ہے جو اپنے کاغذات نامزدگی یا انتخابی حلف ناموں میں غلط معلومات دیتے ہیں، حقائق چھپاتے ہیں یا لازمی تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ سی آر پی سی کی دفعہ 195 بعض مخصوص جرائم کا نوٹس لینے کے معاملے میں عدالت پر پابندی عائد کرتی ہے۔ اس کے مطابق عدالت ان جرائم کا نوٹس اس وقت تک نہیں لے سکتی جب تک کسی مجاز اتھارٹی کی جانب سے تحریری شکایت درج نہ کرائی جائے۔ یعنی عام پولیس رپورٹ یا ذاتی شکایت کی بنیاد پر ان جرائم کا نوٹس نہیں لیا جا سکتا۔ جسٹس دیپانکر دتہ اور جسٹس شیل ناگو کی بنچ نے کہا کہ سی آر پی سی کی دفعہ 195 عدالت کو صرف انہی جرائم کا نوٹس لینے سے روکتی ہے جن کا اس دفعہ میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ عوامی نمائندگی قانون کی دفعہ 125-A میں شامل نہیں ہے، اس لیے عدالتیں اس پابندی کو خود بخود اس جرم پر لاگو نہیں کر سکتیں۔ دراصل سپریم کورٹ کی بنچ راج کمار مڈ کی جانب سے دائر اپیل پر سماعت کر رہی تھی۔ یہ اپیل کرناٹک ہائی کورٹ کے 7 مارچ 2025 کے اس فیصلے کے خلاف تھی، جس میں ہائی کورٹ نے کرناٹک کے رکن اسمبلی ڈاکٹر شیلندر بیلڈالے کے خلاف ان کی شکایت خارج کر دی تھی۔ بنگلورو میں ایک ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ کے سامنے سی آر پی سی کی دفعہ 200 کے تحت دائر شکایت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ 2023 میں بیدر اسمبلی حلقے سے منتخب ہونے والے بیلڈالے نے اپنے نامزدگی کے کاغذات کے ساتھ جمع کرائے گئے حلف نامے میں اپنے رہائشی پتے کے بارے میں غلط معلومات دی تھیں۔

بہار قانون ساز کونسل انتخابات کے لیے رائے دہی مکمل
اساتذہ نشستوں پر 82.85 فیصد اور گریجویٹ نشستوں پر 53.42 فیصد ووٹنگ، 27 اکتوبر کو ووٹوں کی گنتی

آوازِ تسنیم: بہار قانون ساز کونسل کے اساتذہ اور گریجویٹ حلقوں کی 8 نشستوں کے لیے جمعہ کو مکمل ہوئی ووٹنگ کے بعد انتخابی کمیشن کی جانب سے آج جاری کیے گئے حتمی اعداد و شمار کے مطابق، اساتذہ کے انتخابی حلقوں میں 82.85 فیصد اور گریجویٹ انتخابی حلقوں میں 53.42 فیصد ووٹنگ ہوئی۔ اساتذہ کے انتخابی حلقوں میں ووٹروں نے گریجویٹ انتخابی حلقوں کے مقابلے میں زیادہ جوش و خروش دکھایا۔ ووٹنگ کے بعد تمام امیدواروں کی قسمت ووٹوں کے ڈبوں میں بند ہو گئی ہے۔ ووٹوں کی گنتی 27 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق، گریجویٹ انتخابی حلقوں میں پٹنہ، ترہت، دربھنگہ اور کوسی کی نشستوں پر ووٹنگ ہوئی۔ وہیں، اساتذہ کے انتخابی حلقوں میں پٹنہ، سارن، ترہت اور دربھنگہ کی نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ گریجویٹ انتخابی حلقوں میں پٹنہ میں 57.56 فیصد، ترہت میں 48.51 فیصد، دربھنگہ میں 54.73 فیصد اور کوسی میں 54.73 فیصد ووٹنگ درج کی گئی۔ ان چاروں نشستوں پر مجموعی طور پر 53.42 فیصد ووٹنگ ہوئی۔ اساتذہ کے انتخابی حلقوں میں پٹنہ میں 74.75 فیصد، سارن میں 89.05 فیصد، ترہت میں 82.99 فیصد اور دربھنگہ میں 85.87 فیصد ووٹنگ ہوئی۔ اس زمرے میں سارن سب سے آگے رہا۔ اساتذہ کے چاروں انتخابی حلقوں میں مجموعی طور پر 82.85 فیصد ووٹنگ درج کی گئی۔ 8 نشستوں کے اس انتخاب میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور جنتا دل یونائیٹڈ (جے ڈی یو) کے امیدواروں کے علاوہ راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی)، کانگریس، بائیں بازو کی جماعتوں، پرشانت کشور کی جن سوراج پارٹی اور آزاد امیدواروں نے بھی اپنی قسمت آزمائی۔ پٹنہ گریجویٹ انتخابی حلقے میں جے ڈی یو کے نیرج کمار، کانگریس کے ڈاکٹر اسداللہ خان، آر جے ڈی کے دلیپ کمار اور جن سوراج کے ڈاکٹر انوج سنگھ اہم امیدواروں میں شامل ہیں۔ دربھنگہ گریجویٹ نشست پر بی جے پی کے سرویش کمار، کانگریس کے رجنی کانت پاٹھک، آر جے ڈی کے انل کمار جھا اور جن سوراج کے ڈاکٹر محمد امتیاز نورانی کے درمیان مقابلہ ہے۔ ترہت گریجویٹ انتخابی حلقے میں جے ڈی یو کے ابھیشیک جھا، آر جے ڈی کی ڈاکٹر رشمی ونایک گوتم اور جن سوراج کے وی موہن کمار سمیت دیگر امیدوار میدان میں ہیں۔ کوسی گریجویٹ نشست پر بی جے پی کے ڈاکٹر این کے یادو، کانگریس کے منوج کمار جیسوال، آر جے ڈی کے نتیش کمار اور جن سوراج کے رجنیش رنجن اہم امیدوار ہیں۔ اساتذہ کے انتخابی حلقوں میں پٹنہ نشست پر بی جے پی کے نول کشور یادو، کانگریس کے ڈاکٹر سنجے یادو، آر جے ڈی کے سنجیو کمار سنگھ اور جن سوراج کی دویا جیوتی اہم امیدواروں میں شامل ہیں۔ دربھنگہ اساتذہ کی نشست پر جے ڈی یو کے گھنشیام رائے، کانگریس کے ڈاکٹر مدن موہن جھا، آر جے ڈی کے کنور رائے اور جن سوراج کے ایس پی رائے انتخابی میدان میں ہیں۔ ترہت اساتذہ کے انتخابی حلقے میں بی جے پی کے نریندر پرساد سنگھ، بھارتیہ کمیونسٹ پارٹی (سی پی آئی) کے سنجے کمار سنگھ اور جن سوراج کے شیام نندن یادو کے درمیان مقابلہ ہے۔ سارن اساتذہ کی نشست پر جے ڈی یو کے آنند پشکر، آر جے ڈی کے پروفیسر جے رام یادو اور جن سوراج کے آفاق احمد اہم امیدواروں میں شامل ہیں۔ ووٹنگ مکمل ہونے کے بعد اب سب کی نظریں 27 اکتوبر کو ہونے والی ووٹوں کی گنتی پر لگی ہیں۔ گنتی کے بعد ہی واضح ہوگا کہ کس انتخابی حلقے میں کس امیدوار کو کامیابی ملتی ہے اور ان انتخابات میں کس سیاسی جماعت کو برتری حاصل ہوتی ہے۔

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने की रूसी संसद के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन से मुलाकात

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रूस की संघीय संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने तथा दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

बैठक में बिरला ने भारत और रूस के बीच विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 80 वर्ष पूरे होने को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताकर आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने माना कि नियमित संवाद और संसदीय संपर्क द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष ने भारत और रूस की संसदों के बीच अंतर-संसदीय आयोग की अगली बैठक आयोजित करने की संभावनाओं पर विचार करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सांसदों और संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के बीच लगातार संवाद से आपसी समझ बढ़ेगी और साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। बिरला ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत का समर्थन करने के लिए रूस की प्रशंसा की। दोनों नेताओं ने इस चुनौती से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने और विभिन्न देशों के साथ मिलकर प्रभावी प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत की स्थायी सदस्यता के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। ओम बिरला ने इस संबंध में रूस के समर्थन की सराहना की। उन्होंने भारत-रूस संबंधों को और व्यापक बनाने तथा संसदीय सहयोग को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया।

नासिक कुंभ मेला में मंत्री राणे ने की मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की मांग

-कुंभ में केवल हिंदू दुकानदारों को जगह देने की अपील

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री नितेश राणे ने नवी मुंबई में कार्यक्रम के दौरान नासिक कुंभ मेला में मुसलमानों के प्रवेश और दिवाली पर खरीदारी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अगले साल से शुरू होने वाले कुंभ मेला में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही मेला में केवल हिंदू दुकानदारों को दुकानें लगाने की अनुमति देने की बात कही। उनके बयान से धार्मिक आधार पर भेदभाव को लेकर बहस तेज होने की संभावना है।

महायुति सरकार में मंत्री राणे ने कहा कि जिस तरह मुस्लिम धार्मिक संगठन फतवे जारी करते हैं, उसी तरह कुंभ मेला को लेकर भी आदेश जारी होने चाहिए। उन्होंने मुसलमानों के कुंभ मेला में आने पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया।

दिवाली के मौके पर भी मंत्री राणे ने हिंदू व्यापारियों और ग्राहकों से विशेष अपील की। उन्होंने कहा कि हिंदू दुकानदारों को केवल हिंदू ग्राहकों को सामान बेचना चाहिए और हिंदुओं को भी हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी करनी चाहिए। उनके इस बयान को व्यापारिक गतिविधियों में धार्मिक पहचान को प्राथमिकता देने की अपील के रूप में देखा जा रहा है।

नितेश राणे इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। मदरसों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि वहां डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के बजाय आतंकवादी बनाए जाते हैं। हालांकि, यह उनका आरोप था। महाराष्ट्र में कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून को लेकर भी राणे ने सख्त बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कानून के तहत दोषियों को सात साल तक जेल में रहना पड़ सकता है।

वागमण सिमी प्रशिक्षण शिविर मामला : अब्दुल सुभान कुरैशी को सात साल की कठोर कैद

केरल। वर्ष 2007 के वागमण सिमी प्रशिक्षण शिविर मामले में केरल की विशेष अदालत ने आरोपी अब्दुल सुभान कुरैशी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से जुड़े मामलों की विशेष अदालत ने फैसला आरोपी द्वारा अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करने के बाद सुनाया। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत सुनाई गई सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश हफीज मोहम्मद ने महाराष्ट्र के ठाणे निवासी कुरैशी को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 10(ए) के तहत एक साल तथा धारा 20 और 38 के तहत पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी के तहत भी सात-सात साल की कैद का आदेश दिया गया। अदालत ने कुछ धाराओं के तहत 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी पहले जेल में जितनी अवधि बिता चुका है, उस अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने की कथित साजिश में 38 आरोपी शामिल थे। इसी सिलसिले में 10 से 12 दिसंबर 2007 के बीच केरल के वागमण स्थित थंगलपारा में शिविर आयोजित किया गया था। अभियोजन ने आरोप लगाया था कि शिविर में प्रतिभागियों को गोली चलाने, बम बनाने और विस्फोटकों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, मोटरसाइकिल चलाने, चट्टानों पर चढ़ने और जिहाद से संबंधित कक्षाएं आयोजित करने की बात भी सामने आई थी।

झांसी में सड़क जाम और हंगामे के आरोप में पांच किन्नर गिरफ्तार, केस दर्ज

झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में बधाई मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद सड़क पर हंगामा करने और यातायात बाधित करने के आरोप में पुलिस ने पांच किन्नरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनुष्का उर्फ अभिषेक, पूजा, नयनतारा रशियन, ममता और महावीरन के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, इनके खिलाफ बलवा, लोक सेवक को चोट पहुंचाने, सरकारी काम में बाधा डालने, सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध करने, अश्लील हरकत और निषेधाज्ञा के उल्लंघन से संबंधित आरोप लगाए गए हैं।

जहरीली शराब से पार्षद सहित दो की मौत, एक गंभीर

जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के पामगढ़ में जहरीली शराब के सेवन से पार्षद सहित दो लोगों की मौत हो गई. जबकि एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतकों के परिजनों में शोक का माहौल है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शराब पीने के बाद तीनों की तबीयत बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दो लोगों को बचाया नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन सक्रिय हो गए। जहरीली शराब के सेवन की आशंका को देखते हुए मामले की जांच की जा रही है। शराब के नमूनों की जांच और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। घटना ने अवैध शराब के कारोबार और उसकी रोकथाम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कहीं भी होने वाला युद्ध, हर जगह की शांति को खतरे में डालता : जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जारी संघर्षों को लेकर भारत का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को राज्य की नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है। आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं मन सकते है उन्होंने वैश्विक शांति के लिए बातचीत, कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयासों को जरूरी बताया। नई दिल्ली में चिन्मय मिशन की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद विश्व शांति के सामने गंभीर चुनौती है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने की अपील की। उनके मुताबिक, दुनिया के देशों को साझा खतरे के प्रति सतर्क रहने और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होने की जरुरत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि इतिहास से सबक मिलने के बावजूद कुछ देश आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक फायदे और नुकसान को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सभी देश आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति नहीं अपनाते, तब तक इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटना मुश्किल होगा। दुनिया में जारी संघर्षों का उल्लेख कर जयशंकर ने शांति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ÷आज के समय में कहीं भी होने वाला युद्ध, हर जगह की शांति को खतरे में डालता है।÷ उनका यह बयान तब आया है, जब यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं बनी हुई हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान बातचीत और कूटनीति के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। उन्होंने वैश्विक समुदाय से शांति स्थापित करने के लिए मिलकर प्रयास करने की अपील की।

खरगे का नीतीश पर निशाना, समाजवादी विचारधारा के नेता का संघ के साथ जाना दुखद

पटना, एजेंसी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधकर कहा कि समाजवादी विचारधारा से निकले नेता का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की विचारधारा में विश्वास रखने वालों के साथ जाना बहुत दुखद है। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भाजपा और आरएसएस पर भी कई आरोप लगाए।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने डॉ. श्रीकृष्ण सिंह को बिहार में लोकतंत्र की नींव मजबूत करने वाला प्रमुख नेता बताया। उन्होंने कहा कि श्री बाबू ने जमींदारी प्रथा समाप्त करने और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण काम किए। उनके योगदान ने राज्य में सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। कांग्रेस नेता खरगे ने आयोजन समिति का आभार जताकर कहा कि बिहार लोकतांत्रिक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत की भूमि है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने बिहार में कांग्रेस सरकारों के इतिहास का उल्लेख कर कहा कि 1937 में श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली कांग्रेस सरकार बनी थी। इसके बाद 1947 में दूसरी सरकार स्थापित हुई। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन के दौरान मुख्यमंत्री को प्रीमियर कहा जाता था। वर्ष 1952 के पहले विधानसभा चुनाव के बाद श्रीकृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बने रहे और 3 जनवरी 1961 तक इस पद पर बने रहे।

कांग्रेस नेता खरगे ने आरएसएस और भाजपा की विचारधारा की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस की विचारधारा के रहते देश में शांति स्थापित करना मुश्किल होगा। उन्होंने बिहार की जनता से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का समर्थन करने की अपील की और एसआईआर को लेकर लड़ाई को आजादी की दूसरी लड़ाई बताया। राज्यसभा सांसद खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस देश के प्रमुख नेताओं की विरासत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने

कथित 'शुद्धिकरण' की घटना का उल्लेख कर मामले की जांच की मांग भी उठाई। खरगे ने दावा किया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जांच का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में राहुल गांधी के हल्द्वानी दौरे के दौरान उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी गई।

मणिपुर में शांति बहाली के लिए 36 समुदायों की समिति बनेगी: मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह

इंफाल ,एजेंसी। मणिपुर में शांति, सद्भाव और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार सभी 36 समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक समिति गठित करेगी। मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने इसकी जानकारी देकर कहा कि इस पहल का उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच एकता और भाईचारे को बेहतर करना है।

मुख्यमंत्री ने इंफाल स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न जनजातीय प्रमुखों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे राज्य के सभी समुदायों को एकजुट करने के लिए समिति के गठन की संभावनाओं के बारे में पूछा था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल करने का प्रस्ताव तैयार किया। इसके पहले 'मेरा हौ चोंगबा' उत्सव के तहत पैलेस कंपाउंड में पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय प्रमुखों के लिए एक अतिथि गृह का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने÷ पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास तथा भाईचारे का प्रतीक बताया। खेमचंद सिंह ने एंग्लो-मणिपुर युद्ध और वर्ष 1819 से 1826 के दौरान मणिपुर पर बर्मा के कब्जे के कठिन दौर का उल्लेख कर कहा कि राज्य की भूमि, पहचान और विरासत की रक्षा में सभी समुदायों ने योगदान दिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उत्सव से राज्य में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्यमंत्री ने पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की उत्सव में भागीदारी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहले इंफाल आने से हिचकिचाते थे, लेकिन इस बार उनकी भागीदारी सकारात्मक संकेत है। 'मेरा हौ चोंगबा' उत्सव विभिन्न समुदायों के बीच एकता, सद्भाव और पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

2029 तक भारत में चार सक्रिय लांच साइट, इसरो प्रमुख ने भविष्य की योजनाएं बताई

नई दिल्ली , एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के अध्यक्ष वी. नारायणन ने कहा है कि वर्ष 2029 तक भारत में चार सक्रिय प्रक्षेपण स्थल तैयार हो जाएंगे। इससे देश की अंतरिक्ष गतिविधियों का विस्तार होगा और वैश्विक स्तर पर उपग्रह प्रक्षेपण की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसरो का निजीकरण नहीं होगा, हालांकि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों और स्टार्टअप की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।

इसरो प्रमुख नारायणन ने निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इसरो की भावी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तूतीकोरिन जिले के कुलसेकरपट्टिनम में करीब 2,000 एकड़ भूमि पर लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) के लिए अलग प्रक्षेपण परिसर विकसित किया जाएगा। यहां रॉकेट के विभिन्न हिस्सों और प्रणालियों को जोड़ने, प्रक्षेपण की तैयारी, निगरानी, नियंत्रण और आंकड़े प्राप्त करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसरो प्रमुख के अनुसार, अंतरिक्ष क्षेत्र में तेजी से बढ़ती गतिविधियों के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी महत्वपूर्ण है। इसरो स्टार्टअप और निजी कंपनियों को तकनीकी विशेषज्ञता तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगा। इससे आर्थिक विकास को गति मिलने के साथ उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

इसरो प्रमुख नारायणन ने गगनयान मिशन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसरो अगले दो महीनों में पहला मानवरहित परीक्षण करने की योजना बना रहा है। अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने से पहले दो और मानवरहित परीक्षण किए जाएंगे। इन परीक्षणों में सुरक्षा प्रणालियों, वातावरण नियंत्रण, आपातकालीन बचाव व्यवस्था और अंतरिक्ष यान की सुविधाओं की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिशन के लिए जमीन पर लगभग 8,000 प्रयोग पूरे किए जा चुके हैं और चयनित चार अंतरिक्ष यात्री विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं। भविष्य की योजनाओं में चंद्रयान-5 मिशन शामिल है, जो कि जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित करने की योजना है। इसके तहत लगभग 350 किलोग्राम का रोवर चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य है, जो वहां 100 दिनों तक प्रयोग करेगा।

यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेंच, 60 से शुरु होगा मोलभाव

लखनऊ, एजेंसी । उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच गठबंधन में सीटों के बंटवारे का मुद्दा अहम होता जा रहा है। दोनों दलों के बीच सीटों की संख्या को लेकर सहमति बनाना आसान नहीं दिख रहा है। कांग्रेस जहां अधिक सीटों पर चुनाव लड़कर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहती है, वहीं सपा गठबंधन में अपने नेतृत्व और चुनावी रणनीति को प्राथमिकता देना चाहती है। इसके बाद सीटों के बंटवारे पर बातचीत चुनावी प्रदर्शन और जीत की संभावनाओं के आधार पर आगे बढ़ने की उम्मीद है।

चर्चाओं के मुताबिक, कांग्रेस पहले 150 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन अब उसकी दावेदारी 200 सीटों तक पहुंच गई है। दूसरी ओर, सपा अपने आकलन के आधार पर करीब 60 से 65 सीटों से बातचीत शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि, सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच अंतिम सहमति सामने आना बाकी है। सपा अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि गठबंधन में सीटों की संख्या से ज्यादा महत्व जीत की संभावना का है। इसी आधार पर दोनों दलों के संगठन की सक्रियता, स्थानीय नेतृत्व, संभावित प्रत्याशियों और सामाजिक समीकरणों का आकलन किया जा सकता है। बीते चुनावों के नतीजे भी बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल दो सीटों पर जीत मिली थी। सपा के लिए यह प्रदर्शन कांग्रेस की अधिक सीटों की मांग पर सवाल उठाने का आधार बन सकता है। वहीं, कांग्रेस वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को अपनी दावेदारी के समर्थन में रख सकती है। उस चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से सपा को 183 और कांग्रेस को 39 क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। सपा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, पार्टी ने प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों का आकलन किया है। इस आकलन में पिछली जीत के साथ संभावित प्रदर्शन को शामिल किया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि बड़ी संख्या में सीटों पर उसकी स्थिति मजबूत रह सकती है।

हालांकि, सपा के सामने अपने लोकल नेताओं और टिकट के दावेदारों को संतुष्ट रखने की चुनौती भी होगी। जिन क्षेत्रों में पार्टी नेताओं को टिकट मिलने की उम्मीद है, वहां सीट कांग्रेस के खाते में जाने से असंतोष पैदा हो सकता है। दूसरी ओर, कांग्रेस को कम सीटें मिलने पर उसके कार्यकर्ताओं में गठबंधन में सीमित भूमिका का संदेश जाने की आशंका है। इसके बाद दोनों दलों के लिए सीटों की अदला-बदली, प्रत्याशियों की स्वीकार्यता और जीत की संभावना के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण होगा।

गोवा में कन्नड़ बोलने से नहीं मिलेगा वोट, मुख्यमंत्री सावंत का कांग्रेस पर निशाना

पणजी , एजेंसी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस पर निशाना साधकर कहा कि राज्य में कन्नड़ भाषा बोलने से वोट हासिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां के लोग कोंकणी भाषा अच्छी तरह समझते हैं। उनका यह बयान कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के गोवा में कन्नड़ भाषा में दिए गए भाषण को लेकर आया है। दोनों राज्यों में राजनीतिक बयानबाजी के बीच यह मुद्दा चर्चा में है। सीएम सावंत ने मुरगांव तालुका में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कोरटालिम विधानसभा क्षेत्र कार्यालय का उद्घाटन कर यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गोवा की अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान है तथा यहां के मतदाताओं से संवाद करने के लिए लोकल भाषा और भावनाओं को समझना जरूरी है। दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आठ अक्टूबर को कांग्रेस की 'गोय राखण यात्रा' के दौरान कोरटालिम में आयोजित जनसभा को कन्नड़ भाषा में संबोधित किया था।

वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर श्री वाल्मीकि जयंती महोत्सव का किया शुभारंभ तथा वरिष्ठ नागरिकों एवं प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह में की शिरकत

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने रविवार को अलवर के स्वर्ग रोड स्थित श्री महर्षि वाल्मीकि मंदिर में श्री वाल्मीकि जयंती महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगर निगम महापौर श्रीमती सुमनलता अग्रवाल भी उपस्थित रही। साथ ही श्री खांडल विप्र सभा समिति द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिकों एवं प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह में शिरकत की। वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को आत्मसात करने तथा सामाजिक समरसता, सद्भाव और भाईचारे को मजबूत बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन भारतीय समाज को सत्य, धर्म, मर्यादा, कर्तव्यनिष्ठा एवं आदर्श जीवन मूल्यों की प्रेरणा प्रदान करता है। वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने श्री खांडल विप्र सभा समिति द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिकों एवं प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह में वरिष्ठ नागरिकों के अनुभवों एवं समाज के प्रति उनके योगदान की सराहना की तथा प्रतिभावान बच्चों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजनों का सम्मान करना हमारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने प्रतिभावान बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा, अनुशासन, परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प के माध्यम से जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। बच्चों को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए परिवार, समाज और देश का नाम रोशन करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा ने जिन्दौली घाटी रोड निर्माण एवं श्री हनुमान वाटिका के विकास कार्यों का किया निरीक्षण

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संजय शर्मा ने आज उनकी विशेष पहल पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे 52 मोड की जिन्दौली घाटी के पुराने रोड का निर्माण कार्य का पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ बारीकी से निरीक्षण कर निर्माण कार्य को गुणवत्ता के साथ निश्चित समय सीमा में पूर्ण कराने सहित अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान हनुमान वाटिका विकास कार्यों की रूपरेखा का विस्तृत फीडबैक लेकर निश्चित टाइमलाइन में कार्य पूर्ण कराने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर विभागीय अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, प्रबुद्ध नागरिक एवं बड़ी संख्या में बच्चे व आमजन मौजूद रहे।

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की राष्ट्रपति से भेंट

राजस्थान विधान सभा के अमृत महोत्सव के लिए श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को किया आमंत्रित

देवनानी ने राष्ट्रपति को विधान सभा के प्रतीक चिह्न की प्रतिकृति भेंट की

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रायपुर में राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट की। विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को राजस्थान विधान सभा के प्रतीक चिह्न (लोगो) की प्रतिकृति भी भेंट की। राष्ट्रपति से भेंट के दौरान विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव में आयोजित किए जा रहे देशभर की महिला विधायकों के सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। श्री देवनानी ने राष्ट्रपति को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि उनके सानिध्य में राजस्थान विधान सभा को संवैधानिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ करने की प्रेरणा मिलेगी।

देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि राजस्थान विधान सभा वर्तमान में संसदीय लोकतंत्र की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए अपना 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। इन महत्वपूर्ण समारोहों के एक जीवंत और अभिन्न अंग के रूप में, विधान सभा द्वारा 15 जुलाई 2026 को 'पूर्व और वर्तमान सदस्यों का विधायी गौरव यात्रा समागम' आयोजित किया गया। विधान सभा के इतिहास में पहली बार आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन और लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शिरकत की और समारोह को संबोधित किया। इस अनूठी पहल की सभी ने सर्वसम्मति से सराहना की।

देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण के लिए दूरदर्शी कार्य योजना से प्रेरणा लेते हुए, विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका, सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान विधान सभा ने एक विशेष कार्यक्रम महिला विधायक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय उद्देश्यों को सार्थक जमीनी कार्यों में रूपांतरित करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। यह सम्मेलन लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं के योगदान पर विचार-विमर्श के लिए भी उत्कृष्ट मंच बन सकेगा।

देवनानी ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि उनकी उपस्थिति से देश भर की महिला विधायकों का मनोबल, उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा। साथ ही यह सम्मेलन एक अविस्मरणीय आयोजन में भी तब्दील हो जाएगा।

विधान सभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने राष्ट्रपति के साथ राजस्थान विधान सभा की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा के साथ ही पिछले दो वर्षों में राज्य विधान सभा में किए नवाचारों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राजस्थान विधानसभा के नये भवन का उद्घाटन देश के राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमन ने किया था। विधान सभा को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु और श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सम्बोधित कर चुके है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा भी 14 जुलाई, 2023 को विधान सभा को सम्बोधित किया गया था। श्री देवनानी ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु द्वारा उस दौरान दिया गया प्रेरणादायक भाषण राजस्थान विधान सभा की सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। उनके द्वारा दिये गये संदेश विधान सभा को निरन्तर ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।

देवनानी ने राष्ट्रपति को बताया कि विधान सभा के गठन के बाद पहली बार विधान सभा के सभी द्वारों के नाम रखने के साथ ही विधान सभा का प्रतीक चिह्न (लोगो) भी जारी किया गया है। इस लोगो में अशोक चिह्न, राष्ट्रीय ध्वज, विधान सभा का भव्य भवन, राज्य पशु ऊँट, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य वृक्ष खेजड़ी के साथ संस्कृत के ध्येय वाक्य राष्ट्राय धर्मनिष्ठा विधायिका और धान की बाली का समावेश किया गया है।

दीपावली पर अजमेर को बड़ा तोहफा

70 करोड़ की लागत से बनेगा केन्द्रीय बस स्टैण्ड, एडीए कार्यकारी एजेंसी नियुक्त

विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने ली समन्वय बैठक

बस स्टैण्ड का किया अवलोकन, पीडीकोर ने दिया प्रजेंटेशन

50 साल की जरूरतों को पूरा करेगा नया स्टैण्ड

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। दीपावली से पहले राज्य सरकार ने अजमेर को बड़ा तोहफा दिया है। करीब 50 साल पहले बने अजमेर के केन्द्रीय बस स्टैण्ड को पुनः निर्मित किया जाएगा। राज्य सरकार ने अजमेर विकास प्राधिकरण को बस स्टैण्ड निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी बनाया है। करीब 70 करोड़ रूपए की लागत से बस स्टैण्ड को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी की पहल पर तैयार होने वाला यह ड्रीम प्रोजेक्ट आगामी 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। नए बस स्टैण्ड में आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर के सौन्दर्यीकरण और व्यवस्थित यातायात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने रविवार को बस स्टैण्ड के पुनर्विकास को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ पहली समन्वय बैठक की। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) तथा पीडीकोर के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रस्तावित योजना, निर्माण की रूपरेखा, भूमि की उपलब्धता और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को लेकर चर्चा की गई। पीडीकोर की ओर से बस स्टैण्ड के नए स्वरूप को लेकर प्रजेंटेशन भी दिया गया।

विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने कहा कि अजमेर केन्द्रीय बस स्टैण्ड का विकास शहर की बढ़ती जरूरतों और भविष्य की यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बस स्टैण्ड का नया डिजाइन आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर के सौन्दर्यीकरण को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इसमें गार्डन, आकर्षक स्टैच्यू, बेहतर लाइटिंग और आधुनिक संरचनाओं का समावेश होगा। यात्रियों को सुविधाजनक आवागमन, बेहतर प्रतीक्षालय और व्यवस्थित बस संचालन की सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित योजना में हाई-राइज प्लेटफार्म, डिजिटल डिस्प्ले, बसों की रियल टाइम लोकेशन की जानकारी, ई-बस चार्जिंग स्टेशन, डीजल पम्प तथा आधुनिक सुविधाओं से युक्त कार्यालयों की व्यवस्था शामिल होगी। वॉल्वो और एसी बसों सहित विभिन्न शहरों के लिए अलग-अलग प्लेटफार्म विकसित करने की योजना भी बनाई जा रही है। इससे यात्रियों को अपनी बस तक पहुंचने में सुविधा होगी और बसों का संचालन अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। बस स्टैण्ड के पुनर्विकास के तहत वर्तमान वर्कशॉप को जयपुर रोड पर स्थानांतरित किया जाएगा। रोडवेज की ओर से एडीए को कुछ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि की उपलब्धता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे। वर्कशॉप स्थानांतरित होने से बस स्टैण्ड परिसर का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा तथा यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होगा। श्री देवनानी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बस स्टैण्ड के पुनर्विकास की योजना को सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ाया जाए। निर्माण कार्य में आधुनिक तकनीक, यात्रियों की सुविधा, सुगम यातायात और भविष्य की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि अजमेर के केन्द्रीय बस स्टैण्ड को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने से शहर की परिवहन व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और अजमेर आने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने रोडवेज बस स्टैण्ड का निरीक्षण भी किया। उन्होंने प्रस्तावित विकास कार्यों के मद्देनजर परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा अधिकारियों के साथ आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की।

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान

बीकानेर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, बीछवाल स्थित गोदाम से 22 हजार किलो खाद्य तेल सीज

नेपाल में निर्मित CHOICE सनफ्लावर ऑयल की भ्रामक लेबलिंग एवं प्रचार के मामले में जांच

एक दिन में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, खाद्य पदार्थों के 6 नमूने लिए

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन तथा प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्रीमती गायत्री राठौड़ के निर्देशन में आमजन को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण अविचल चतुर्वेदी के निर्देशानुसार, अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के मार्गदर्शन एवं संयुक्त आयुक्त वी.पी. शर्मा के पर्यवेक्षण में केंद्रीय खाद्य सुरक्षा दल ने बीकानेर में कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों के कुल 6 नमूने जांच के लिए लिए गए तथा बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित गोदाम से करीब 22,000 किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया।

खाद्य तेल के गोदाम पर कार्रवाई, 22 हजार किलो तेल सीज

खाद्य सुरक्षा दल ने बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स लक्ष्मी नारायण भंवर लाल के गोदाम का निरीक्षण किया। यहां से करीब 22 हजार किलोग्राम खाद्य तेल सीज किया गया। सीज किए गए तेल में नेपाल में निर्मित CHOICE ब्रांड का सनफ्लावर ऑयल तथा 'बाबा रामदेव छाप' सरसों का तेल शामिल है। कार्रवाई के दौरान जांच के लिए खाद्य तेल के तीन नमूने भी लिए गए। ÒCHOICEÓ सनफ्लावर ऑयल की लेबलिंग एवं प्रचार से जुड़े पहलुओं की जांच की जा रही है।

दो अन्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण

खाद्य सुरक्षा दल ने मैसर्स नागड़ नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज का निरीक्षण कर नारियल पेड़ा खाद्य सामग्री का एक नमूना जांच के लिए लिया। वहीं, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स बिशनलाल बाबूलाल की निर्माण इकाई का निरीक्षण कर दो खाद्य नमूने लिए गए।

इस प्रकार एक ही दिन में तीन प्रतिष्ठानों से कुल 6 खाद्य नमूने जांच के लिए लिए गए। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में संबंधित फर्मों को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए जाएंगे।

त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने कहा कि दीपावली पर्व के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा मिलावट तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य तेल, घी, मावा, मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय की गहन जांच की जा रही है।

उन्होंने कहा कि भ्रामक लेबलिंग, अनुचित प्रचार तथा मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों के कारोबार पर विभाग की कड़ी नजर है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध खाद्य नमूनों की जांच, खाद्य पदार्थों को सीज करने, लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त करने तथा प्रकरण की प्रकृति के अनुसार अभियोजन सहित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित मानकों के अनुरूप सुरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने तथा पैकेजिंग और लेबलिंग संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विस लीग' संगठन का गोल्डन जुबली समारोह

समाज में एकता, सहयोग और स्थिरता में पूर्व सैनिकों की महती भूमिका

पूर्व सैनिकों का सम्मान और उनका कल्याण हमारी परम्परा–राज्यपाल

द अनकवर्ड अपडेट

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि पूर्व सैनिकों का सम्मान और उनका कल्याण हमारी परम्परा और संस्कृति है। उन्होंने देश की सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने में भारतीय सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी सैनिक अपने अनुशासन, अनुभव और नेतृत्व क्षमता से बहुत से स्तरों पर राष्ट्र विकास में सहयोग दे रहे हैं। समाज में एकता, सहयोग और स्थिरता में भी उनकी महती भूमिका है। बागडे रविवार को जिला पूर्व सैनिक संघ, जयपुर द्वारा आयोजित 'जयपुर डिस्ट्रिक्ट एक्स सर्विसेज लीग' संगठन के गोल्डन जुबली आयोजन समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए भारत सरकार ने लम्बे समय से लंबित 'वन रैंक वन पेंशन' योजना लागू करके उनको अधिकार देने का महती कार्य किया है। राजस्थान में भी पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान, सुरक्षा और पेंशन लाभों में निरंतर वृद्धि की गई है। एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के माध्यम से राजस्थान में 13 हजार से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित करने की पहल की गई है ताकि पूर्व सैनिकों और उनके आश्रित परिवारजनों को यथा–समय समुचित सहायता मिल सके। इसी तरह पूर्व सैनिकों के बच्चों हेतु कोचिंग सहायता राशि भी बढ़ाकर हमने 15 हजार से अब 25 हजार कर दी है। राज्य सरकार स्तर पर राज्यभर में पिछले कुछ समय के दौरान 14 हजार से अधिक वीरांगनाओं के सम्मान की पहल हुई है। राज्यपाल ने कहा कि सैनिक जब सीमा पर हमारे लिए लड़ता है तो उसका सबसे बड़ा सम्बल उसका परिवार ही होता है। इसलिए सैनिकों के आश्रितों, परिवारजनों का कल्याण भी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होना चाहिए। उन्होंने पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए कहा कि दशकों के अनुभव, नेतृत्व, अनुशासन और रणनीतिक सोच को वही समाज में लाते हैं।

राजस्थान में प्राकृतिक एवं योगिक खेती को मिलेगी नई पहचान, कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच ऐतिहासिक समझौता

ग्लोबल समिट में हुआ एमओयू, प्रदेशभर में प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

किसानों को मिलेगा प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण, कृषि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए राजयोग, तनाव प्रबंधन और क्षमता संवर्धन कार्यक्रम होंगे आयोजित

आबूरोड स्थित तपोवन को योगिक प्राकृतिक खेती के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल

आवाज़ ए तसनीम

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियों के विस्तार की दिशा में कृषि विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। रविवार को आबूरोड स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर में आयोजित ग्लोबल समिट के दौरान राजस्थान सरकार के कृषि विभाग एवं ब्रह्माकुमारी संस्थान की राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग के मध्य महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। राजस्थान सरकार की ओर से कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। वहीं, ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग की अध्यक्ष बीके सरला के प्रतिनिधित्व में यह समझौता संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक पहल से प्रदेश में प्राकृतिक एवं योगिक खेती के विस्तार, किसानों के प्रशिक्षण, कृषि कार्मिकों के क्षमता संवर्धन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को नई गति मिलेगी। समझौते के माध्यम से कृषि विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता और ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता संबंधी अनुभवों का समन्वय किया जाएगा।

प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता : कृषि आयुक्त

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल एवं किसान हितैषी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन तथा किसानों की दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है। गोयल ने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए किसानों को तकनीकी जानकारी के साथ निरंतर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण एवं सफल कृषि मॉडल से जोड़ना आवश्यक है। कृषि विभाग और ब्रह्माकुमारी संस्थान के संयुक्त प्रयास इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एवं कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीना पूर्व में ब्रह्माकुमारी संस्थान के प्राकृतिक खेती मॉडल का अवलोकन कर इसकी सराहना कर चुके हैं।

प्रदेशभर में किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण, गांव-गांव पहुंचेगी प्राकृतिक खेती की तकनीक

समझौते के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में किसानों के लिए प्राकृतिक एवं टिकाऊ खेती से संबंधित प्रशिक्षण शिविर, कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां तथा जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, स्थानीय संसाधनों से कृषि आदान तैयार करने, जल संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों तथा टिकाऊ कृषि प्रबंधन की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही किसानों को सफल प्राकृतिक खेती मॉडल का प्रत्यक्ष अवलोकन कराने के लिए शैक्षणिक भ्रमण एवं अनुभव साझा करने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि किसान इन पद्धतियों को अपनी खेती में अपनाने के लिए प्रेरित हो सकें।

कृषि कार्मिकों के क्षमता संवर्धन पर विशेष जोर, तैयार होंगे मुख्य प्रशिक्षक

इस समझौते का लाभ किसानों के साथ-साथ कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, कृषि पर्यवेक्षकों एवं क्षेत्रीय कार्मिकों को भी मिलेगा। दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में कृषि कार्मिकों को प्राकृतिक खेती की नवीन तकनीकों, प्रभावी कृषि प्रसार गतिविधियों एवं किसानों को बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करने के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे, जो आगे जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर किसानों तथा कृषि कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे।

तपोवन बनेगा योगिक प्राकृतिक खेती का उत्कृष्टता केंद्र

समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता आबूरोड स्थित तपोवन को योगिक प्राकृतिक खेती के उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक सहमति है। आवश्यक शासकीय स्वीकृतियों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं के अधीन प्रस्तावित यह केंद्र प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, अनुसंधान, ज्ञान-विनिमय एवं क्षमता संवर्धन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सकेगा। यहां किसानों, कृषि अधिकारियों एवं मुख्य प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती के मॉडल प्रदर्शन तथा शैक्षणिक भ्रमण जैसी गतिविधियां आयोजित की जा सकेंगी। केंद्र के संस्थागत स्वरूप, आधारभूत सुविधाओं, वित्तीय व्यवस्था एवं संचालन संबंधी विषयों पर पृथक से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जाएंगी।

कृषि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक कार्य संस्कृति पर भी ध्यान

एमओयू के अंतर्गत कृषि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, कार्यक्षमता एवं सकारात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।

स्वामी और प्रकाशक रमाकांत गोस्वामी एवं मुद्रक ताराचंद कुमावत द्वारा महारानी प्रिन्टर्स, 17 मां वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड़ जयपुर छपवाकर/मुद्रित कर, 10 MA, आईजी नगर, जगतपुरा,जयपुर, राजस्थान - 302017 से प्रकाशित किया। संपादकः रमाकान्त गोस्वामी, उप संपादक - मोनिका शर्मा, पीआरजीआई नं. RJBIL/25/A1815 ब्रांच ऑफिसः 18k3, पंकज सिंघवी मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302002, मो. नं. 7610866001, हैल्प लाईन नं.: 8946840063, ईमेल आईडीः tasneemtv.official @gmail.com, वेबसाइटः www.tasneemtv.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी. आर. पी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तदायी), किसी भी वाद-विवाद से निपटने के लिए न्यायालय जयपुर मान्य होगा।